



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### रुड़की

खण्ड-23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 03, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-52

#### विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग—अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग—अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक घन्डा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	₹0
भाग 1—विज्ञप्ति—अधिकार, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	971-1011	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आझाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल नहोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	873-874	1500
भाग 2—आझाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़—पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइल ऐरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) सभा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों द्वारा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कूमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निवाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	703-724	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़—पत्र आदि	—	1425

## भाग १

विज्ञाप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे दैयकितक नोटिस

## गृह अनुमान—३

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2022 ई०

संख्या 315/XX-3/2022-2(4)/2013(पार्ट II)—राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा (संशोधन)  
नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (i) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 है।  
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-१८ का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहाँ आगे भूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-१ में दिये गये विद्यमान नियम १८(ख) के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-१  
(विद्यमान नियम)

## (ख) बुलावा पत्र

निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जांचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जिलावार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के मर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा-कोड/ नाम/ पता और परीक्षा केन्द्र स्थल

स्तम्भ-२  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

## (ख) बुलावा पत्र

निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जांचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जिलावार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के मर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा-कोड/ नाम/ पता और परीक्षा केन्द्र स्थल

मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से दिनांक और समय सहित, परीक्षा-कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाम—जोख पुरुष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट—2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट—2(ख)(१) एवं पुरुष अग्निशामन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट—3(क), महिला अग्निशामन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट—3(ख)(१) के अनुसार होंगे।

आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाम जोख पुरुष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट—2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट—2(ख)(१) एवं पुरुष अग्निशामन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट—3(क) महिला अग्निशामन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट—3(ख)(१) के अनुसार होंगे।

### परिशिष्ट २(क) का संशोधन

3.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—१ में वी ग्रही विद्यमान परिशिष्ट—२(क) के क्रम संख्या—१ में दिये उपर्युक्त के स्थान पर स्तम्भ २ में दिया गया उपर्युक्त रख दिया जायेगा, अर्थात् —

#### स्तम्भ—१

##### (विद्यमान उपर्युक्त)

१— अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है—

#### ऊँचाई

- (१) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम— १६८ सेंटीमीटर
- (२) पर्वतीय क्षेत्र हेतु— १६० सेंटीमीटर
- (३) अनुसूचित जनजाति हेतु— १५७.५ सेंटीमीटर

#### स्तम्भ—२

##### (एतद्वारा प्रतिस्थापित उपर्युक्त)

१— अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है—

#### ऊँचाई

- |  |                 |
|--|-----------------|
| (१) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम— | १६५ सेंटीमीटर   |
| (२) पर्वतीय क्षेत्र हेतु—  | १६० सेंटीमीटर   |
| (३) अनुसूचित जनजाति हेतु—  | १५७.५ सेंटीमीटर |

#### सीने की भाप

#### सीने की भाप

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	८१.३ सेमी०	८८.३ सेमी०

सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	बिना फुलाये	फुलाने पर
	८१.३ सेमी०	८८.३ सेमी०

टिप्पणी— सीने में न्यूनतम ०६ सेमी० का फुलाव अवश्यक है।

टिप्पणी— सीने में न्यूनतम ०५ सेमी० का फुलाव अनिवार्य है।

**परिशिष्ट ३(क) का संशोधन**

५.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-१ में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट-३(क) के क्रम संख्या-१ में दिये उपबंध के स्थान पर स्तम्भ २ में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात्,

**स्तम्भ-१**  
(विद्यमान उपबंध)

१— अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः—

**ऊँचाई**

(१) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम—  
167.7 सेंटीमीटर

(२) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए—  
160.0 सेंटीमीटर

(३) पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए—  
162.8 सेंटीमीटर

**सीने की माप**

सामान्य व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये	विना फुलावे	फुलावे पर
	78.5 सेमी०	83.8 सेमी०
अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये	78.5 सेमी०	81.5 सेमी०

टिप्पणी:- न्यूनतम ०५ सेमी० का फुलाव अनिवार्य अनिवार्य है।

**परिशिष्ट २(क)१ का संशोधन**

६.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-१ में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट-२(क)१ के स्थान पर स्तम्भ-२ में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात् :-

**स्तम्भ-१**

## (विद्यमान परिशिष्ट)

परिशिष्ट-२(क)(१) (नियम १८(ख) देखे)  
महिला अग्निशामक (फायरबैन) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाम—जोख

**स्तम्भ-२**

## (एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)

परिशिष्ट-२(क)(१) (नियम १८(ख) देखे)  
महिला अग्निशामक (फायर बुमेन) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाम—जोख

2— महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः—

छैचार्ड

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग—152 सेंटीमीटर
- (2) अनुसूचित जनजाति हेतु— 147 सेंटीमीटर
- (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु— 147 सेंटीमीटर

वजन— न्यूनतम 45 किंग्राम होना अनिवार्य है।

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः—

छैचार्ड

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति— 152 सेंटीमीटर
- (2) अनुसूचित जनजाति हेतु— 147 सेंटीमीटर
- (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु— 147 सेंटीमीटर

वजन— न्यूनतम 45 किंग्राम होना अनिवार्य है।

परिशिष्ट 3(क)1 का संशोधन

6.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट—3(क)1 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दी गयी परिशिष्ट सख दी जायेगी, अर्थात् :-

**स्तम्भ—1**

(विद्यमान परिशिष्ट)

परिशिष्ट—3(क)(1)(नियम 18(ख) देखें)

महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टैशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी मर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप—जोख

2— महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः—

**स्तम्भ—2**

(एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)

परिशिष्ट—3(क)(1) (नियम 18(ख) देखें)

महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टैशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी मर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप—जोख

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैः—

छैचार्ड

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग— 152 सेंटीमीटर
- (2) अनुसूचित जनजाति हेतु— 147 सेंटीमीटर
- (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु— 147 सेंटीमीटर

टिप्पणी— वजन न्यूनतम 45 किंग्राम होना टिप्पणी— वजन न्यूनतम 45 किंग्राम होना अनिवार्य है। अनिवार्य है।

छैचार्ड

- (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति हेतु— 152 सेंटीमीटर
- (2) अनुसूचित जनजाति हेतु— 147 सेंटीमीटर
- (3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु— 147 सेंटीमीटर

परिशिष्ट 2(ख)1 का संशोधन

7.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट—2(ख)1 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दी गयी परिशिष्ट सख दी जायेगी, अर्थात् :-

## स्तम्भ—१

(विद्यमान परिशिष्ट)

परिशिष्ट—२(ख)(१) (नियम १८(ग))  
देखो; महिला अग्निशामक (फायर ब्रुमेन) की  
सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता  
परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अस्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशामन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

२— महिला अस्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
१	फ्रिकेट बाल थो (पूर्णांक २० अंक)	१८ मीटर २० मीटर २४ मीटर २८ मीटर ३२ मीटर	१० १२ १४ १६ २०
२	लम्बी यूट (पूर्णांक २० अंक)	८ फिट ९ फिट १० फिट ११ फिट १२ फिट १३ फिट	१० १२ १४ १६ १८ २०
३	दौड़ ८० मीटर (पूर्णांक २०)	१८ सेकेण्ड १५ सेकेण्ड १४ सेकेण्ड १३ सेकेण्ड १२ सेकेण्ड ११ सेकेण्ड	१० १२ १४ १६ १८ २०
४	शटल रेस (२५×४ मीटर) (पूर्णांक २०)	२९ सेकेण्ड २८ सेकेण्ड २७ सेकेण्ड २६ सेकेण्ड	१० १४ १८ २०
५	स्किपिंग (पूर्णांक २०)	५५ बार ०१ मिनट ४० बार ०१ मिनट ६५ बार ०१ मिनट ७० बार ०१ मिनट ७५ बार ०१ मिनट ८० बार ०१ मिनट	१० १२ १४ १६ १८ २०

## स्तम्भ—२

(एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)

परिशिष्ट—२(ख)(१) (नियम १८(ग) देखो) महिला अग्निशामक (फायर ब्रुमेन) की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अस्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशामन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
१	फ्रिकेट बाल थो (पूर्णांक २० अंक)	१८ मीटर २० मीटर २४ मीटर २८ मीटर ३२ मीटर	१० १२ १४ १६ २०
२	लम्बी यूट (पूर्णांक २० अंक)	८ फिट ९ फिट १० फिट ११ फिट १२ फिट १३ फिट	१० १२ १४ १६ १८ २०
३	दौड़ ८० मीटर (पूर्णांक २०)	१८ सेकेण्ड १५ सेकेण्ड १४ सेकेण्ड १३ सेकेण्ड १२ सेकेण्ड ११ सेकेण्ड	१० १२ १४ १६ १८ २०
४	शटल रेस (२५×४ मीटर) (पूर्णांक २०)	२९ सेकेण्ड २८ सेकेण्ड २७ सेकेण्ड २६ सेकेण्ड	१० १४ १८ २०
५	स्किपिंग (पूर्णांक २०)	५५ बार ०१ मिनट ४० बार ०१ मिनट ६५ बार ०१ मिनट ७० बार ०१ मिनट ७५ बार ०१ मिनट ८० बार ०१ मिनट	१० १२ १४ १६ १८ २०

शारीरिक मानक परीक्षा में आई पाई गई महिला अग्निशामक अस्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक १००), न न्यूनतम ५० अंक प्राप्त करना करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेन्ट में ५० प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में महिला

आधिकारी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।

(1) महिला अधिकारीयों की संख्या एक विन में सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होगी जिससे परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो।

(2) शारीरिक दक्षता परीक्षण के परिणाम उसी विन सूचना पटद् पर प्रदर्शित किये जावेंगे।

(3) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

आशा से,

राधा रत्नाली,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 315/XX-3/2022-2(4)2013(part-II), dated November 28, 2022 for general information.

#### NOTIFICATION

November 28, 2022

No. 315/XX-3/2022-2(4)2013(part-II)—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of "Constitution of India" Governor is please to make the following rules with objective to further amend the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers/Employees Service (Amendment) Rules, 2022 :—

#### The Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service (Amendment) Rules, 2022.  
 (2) It shall come into force at once.

**Amendment of rule 16**

2.

In the Uttarakhand Fire and Emergency Service Subordinate officers / Employees Service Rules, 2016, (here in after referred as principal Rules) for the existing rule 16(b) as set out in column-1 below the rule as set out in column-2, shall be substituted, namely:-

**Column-1  
Existing rule**

**(b) Call letter:**

All the forms received in commission till stipulated date shall be examined. After examination the district wise list of such candidates whose application forms proper, shall be provided to the police headquarter. The police headquarters shall made available the list to concerned centre incharge of the district centre authorised for recruitment. The centre incharge of the concerned district shall issue admit card for physical standard test, physical efficiency test to the candidates. The date with time, examination code/ name address and examination centre for physical efficiency test. Physical standard test shall be clearly mentioned in the admit cards.

Physical standard test shall be according for to male fireman in Appendix 2(A), female fireman in appendix 2(A)(1) and male Fire station second officer in appendix 3(A) and appendix 3(A)(1) for female Fire station second officer.

**Amendment of  
Appendix 2(A)**

3.

In the principal rules for the provision given in serial number-1 of the existing Appendix-2(A) set out in column-1 below, the provision set out in column-2, shall be substituted, namely:-

**Column-2 ~  
Rule hereby substituted**

**(b) Call letter:**

All the forms received in commission till stipulated date shall be examined. After examination the district wise list of such candidates whose application forms shall find proper, shall be provided to the police headquarter. The police headquarters shall made available the list to concerned centre incharge of the district centre authorised for recruitment. The centre incharge of the concerned district shall issue admit card for physical standard test, physical efficiency test to the candidates. The date with time, examination code/ name address and examination centre for physical efficiency test. Physical standard test shall be clearly mentioned in the admit cards.

Physical standard test shall be according for to male fireman in Appendix 2(A), female fireman in appendix 2(A)(1) and male Fire station second officer in appendix 3(A) and appendix 3(A)(1) for female Fire station second officer.

<b>Column-1</b>	<b>Column-2</b>
<b>Existing Provision</b>	<b>Provision hereby substituted</b>

- 1- The minimum physical standard for candidates as follows-

- 1- The minimum physical standard for candidates as follows-

**Height:**

- (1) for General/ other backward classes and Scheduled Castes – 168 Cm
- (2) For hill area candidates- 160 Cm
- (3) Scheduled tribes- 157.5 Cm

**Height:**

- (1) for General/ other backward classes and Scheduled Castes- 165 Cm
- (2) For hill area candidates- 160 Cm
- (3) Scheduled tribes- 157.5 Cm

**Chest Measurement:**

- (1) For All categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm.

**Chest Measurement:**

- (1) For All categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm.

Note: A minimum of 5 centimeter expansion in chest is essential.

**Amendment of Appendix 3(A)**

4.

In the principal rules for the provisions given in serial number-1 of the existing Appendix-3(A) set out in column-1 below, the provision set out in column-2, shall be substituted, namely;

<b>Column-1</b>	<b>Column-2</b>
<b>Existing Provisions</b>	<b>Provisions hereby substituted</b>

- 1- The minimum physical standard for candidates as follows-

- 1- The minimum physical standard for candidates as follows-

HeightHeight

(1) General/ other backward classes and Scheduled Castes – 167.7 cm

((1) General/ other backward classes and Scheduled Castes – 167.7 cm

(2) Scheduled Tribes- 160 cm

(2) Scheduled Tribes- 160 cm

(3) For hill area candidates- 162.6 cm

(3) For hill area candidates- 162.6 cm

Chest Measurement:

for candidate of General and others categories	<u>before expansion</u>	<u>on expansion</u>
	78.8 cm	83.8 cm
for candidates of Scheduled Tribes and hilly area	76.5 cm	81.5 cm

Note: A minimum of 5 centimeter expansion is essential.

Chest Measurement:

for candidate of General / other backward classes and Scheduled Castes	<u>before expansion</u>	<u>on expansion</u>
	78.8 cm	83.8 cm

  

for candidates of Scheduled Tribes and hilly area	<u>before expansion</u>	<u>on expansion</u>
	76.5 cm	81.5 cm

Note: A minimum of 5 centimeter expansion in chest is essential.

**Amendment of Appendix 2(A) (1)**

5. In the principal rules for the existing Appendix-2(A) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

**Column-1****Existing Appendix****Appendix 2(A)(1): rule 16(b)**

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fireman (firemen);

The minimum physical standard for female is as follows-

**Height**

(1) General/ other backward classes- 152 cm

**Column-2****Appendix hereby substituted****Appendix 2(A)(1): rule 16(b)**

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female fireman (fire woman);

The minimum physical standard for female is as follows-

**Height**

(1) General/ other backward classes and Scheduled Castes - 152 cm

(2) Scheduled Tribes- 147 cm

(2) Scheduled Tribes- 147 cm

(3) For hill area candidates- 147 cm

(3) For hill area candidates- 147 cm

**Weight:** Minimum 45 in essential.**Weight:** Minimum 45 in essential.**Amendment of  
Appendix 3(A) (1)**

6.

In the principal rules for the existing Appendix-3(A) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

**Column-1****Existing Appendix****Appendix 3A (1) see rule 16 (b):**

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fire Station Second Officer-

The minimum physical standard for female is as follows-

**Column-2****Appendix hereby substituted****Appendix 3A (1) see rule 16 (b):**

The physical standard test for direct recruitment to the posts of female Fire Station Second Officer-

The minimum physical standard for female is as follows-

**Height**

(1) General/ other backward classes

-152 cm

(2) Scheduled Tribes-147 cm

(3) For hill area candidates- 147 cm

**Height**

(1) General/ other backward classes and

Scheduled Castes -152 cm

(2) Scheduled Tribes-147 cm

(3) For hill area candidates- 147 cm

**Weight:** Minimum 45 in essential.**Weight:** Minimum 45 in essential.**Amendment of  
Appendix 2(B) (1)**

7.

In the principal rules for the existing Appendix-2(B) (1) set out in column-1 below the Appendix set out in column-2, shall be substituted, namely;

**Column-1****Existing Appendix****Appendix 2(B)(1) rule 16(c):**

The Physical efficiency test for direct recruitment to the post of Fireman (Female):

The candidates declared successful in physical standard test shall be required to take part in physical efficiency test.

The physical efficiency test for fireman (female) and fire station second officer (female) shall be conducted as mentioned below:-

2. The minimum physical efficiency test for female candidates shall be as follows-

No.	name of the event	distance/time	marks
1	Cricket ball throw (total marks 20)	16 meter	10
		20 meter	12
		24 meter	14
		28 meter	16
		32 meter	20
2	Long jump (total mark 20)	8 feet	10
		9 feet	12
		10 feet	14
		11 feet	16
		12 feet	18
		13 feet	20
3	Race 50 meter (total marks 20)	16 second	10
		18 second	12
		14 second	14
		15 second	16
		13 second	18
		11 second	20

**Column-2****Appendix hereby substituted****Appendix 2(B)(1) rule 16(c):**

The Physical efficiency test for direct recruitment to the post of Fireman (Female):

The candidates declared successful in physical standard test shall be required to take part in physical efficiency test.

The physical efficiency test for fireman (female) and fire station second officer (female) shall be conducted as mentioned below:-

No.	name of the event	distance/time	marks
1	Cricket ball throw (total marks 20)	16 meter	10
		20 meter	12
		24 meter	14
		28 meter	16
		32 meter	20
2	Long jump (total mark 20)	8 feet	10
		9 feet	12
		10 feet	14
		11 feet	16
		12 feet	18
		13 feet	20
3	Race 50 meter (total marks 20)	16 second	10
		18 second	12
		14 second	14
		15 second	16
		13 second	18
		11 second	20

	4	Shuttle Race (25*4 meter) (marks 20)	28 second	10		4	Shuttle Race (25*4 meter) (marks 20)	28 second	10
			28 second	14				28 second	14
			27 second	18				27 second	18
			26 second	20				26 second	20
	5	skipping (total marks 20)	88 time of minutes	10		5	skipping (total marks 20)	88 time of minutes	10
			80 time of minutes	12				80 time of minutes	12
			88 time of minutes	14				88 time of minutes	14
			70 times of minutes	16				70 times of minutes	16
			78 time of minutes	18				78 time of minutes	18
			80 times of minutes	20				80 times of minutes	20

The female fireman candidates found qualified in the physical standard test shall be required to obtain a minimum of 50 marks in the physical efficiency test (total-100) as per the following details and in case of getting less than 50 percent marks in any event, the female candidate shall be given the same level But shall be excluded from the selection process.

(1) The number of candidates shall not be more than 100 in one day for each such team so as not to affect the quality and process of the tests.

(2) The result of physical efficiency test shall be made available to the candidate on the same day. The results of candidates shall be displayed on the Notice Board.

(3) Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical efficiency test examination.

By Order

RADHA RATURI,  
Additional Chief Secretary.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग १

### विज्ञप्ति/पदोन्नति

०८ नवम्बर, २०२२ ई०

संख्या 1008/XIX-1/2022/203 खाद्य/2011-जिला पूर्ति अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स रु० ५८,१००-१,७७,५०० (लेवल-१०) के रिक्त पद हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिहार की व्यवस्था के आधार पर श्री कोहली हीनीय खाद्य अधिकारी को एतद्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स रु० ५८,१००-१,७७,५०० (लेवल-१०) के पद पर पदोन्नत करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान स्थान पर ही रैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२-पदोन्नति के प्रत्यक्षरूप श्री कोहली को ०१ वर्ष की दिल्लित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

३-श्री कोहली को निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता पद पर लक्ष्यात अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यगार प्रमाणक सम्बन्धी सूचना शासन/आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहसदून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

४-श्री कोहली के रैनाती आदेश पृथक से किये जायेंगे।

५-चक्र पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अन्य कार्यिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होने की स्थिति में, तदपरिणाम से इस आदेश को तत्काल में निर्वाचित होने वाली विषिता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,

सचिव।

## सिंचाई एवं बाध नियंत्रण अनुभाग-०२

### अधिसूचना

३० नवम्बर, २०२२ ई०

ई० पत्रावली संख्या 20742 एतद्वारा सौंग बाध प्रयोजन के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों हेतु “सौंग बाध प्रयोजन एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति-२०२२” (हिन्दी/अंग्रेजी) अधिसूचित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

# सौंग बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु नीति का आलेख

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित  
प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३  
में उल्लेखित प्रावधानानुसार)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

## **१. प्रस्तावना**

प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना देहरादून के भविष्य की पेयजल आपूर्ति हेतु अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजना के निर्माण से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए १५० एम०एल०डी० (१७५ क्यूमेक) पेयजल की आपूर्ति ब्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे वर्ष २०५१ तक लगभग १० लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

वर्तमान में देहरादून शहर की पेयजल व्यवस्था लगभग पूर्ण रूप से नलकूपों पर निर्भर है, भविष्य में पेयजल व्यवस्था हेतु अन्य सतही जल स्रोतों (Surface water resources) का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा, जिससे जल आपूर्ति की सापेक्षणीय (sustainable) योजना तैयार की जा सके एवं सतही जल स्रोतों एवं भूजल स्रोतों में समन्वय बना रहे उक्त परियोजना के निर्माण से भविष्य में नलकूपों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आने के कारण नलकूपों के निर्माण एवं उन पर किये जाने वाले भारी विद्युत व्यय संबालन तथा रखरखाव व्यय में भी भारी कमी आयेगी। निर्मित जलाशय एवं भूजल दोहन में कमी आने के कारण भूजल स्तर में बढ़ि होगी।

सौंग बांध पेयजल परियोजना सौंग नदी पर प्रस्तावित है और यह देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल जिले की सीमा पर स्थित ग्राम सौंदणा (देशान्तर ७८°११'३०"ई० और अक्षांश ३०°१८'०४" एन०) में, देहरादून से लगभग २५ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस परियोजना के अन्तर्गत सौंग नदी पर १३०.६० मी० (From deepest foundation level) ऊंचाई के बांध का निर्माण प्रस्तावित है।

जलाशय निर्माण के फलस्वरूप ढूब क्षेत्र से ०३ ग्राम क्रमशः प्लेड (देहरादून), रांगड़गाँव (टिहरी गढ़वाल) एवं घुडसालगांव (टिहरी गढ़वाल) प्रभावित होंगे तथा बांध के खनन क्षेत्र, बैचिंग प्लाट एवं मिक्सिंग प्लाट के लिये ली जाने वाली भूमि से ०१ ग्राम सौंदणा (टिहरी गढ़वाल) प्रभावित होंगा। इस प्रकार परियोजना के निर्माण से कुल ०४ ग्राम प्रभावित होंगे।

यह पुनर्वास नीति इस बांध के निर्माण से प्रभावित होने वाली जनसंख्या पर लागू होगी तथा प्रभावित ग्रामों की जनसंख्या को विस्थापित किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का अधिनियम संख्या ३०) के प्रावधानानुसार यह नीति बनायी जा रही है।

## **२. पुनर्वास नीति के संदेश**

- २.१ सौंग बांध परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास नीति के उद्देश्य निम्नानुसार है।
  - (क) जहाँ तक सम्भव हो, न्यूनतम विस्थापन करने, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना।
  - (ख) प्रभावित व्यवितर्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- (ग) समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक तथा सबेदनशीलता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- (घ) प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना।
- (ङ) पुनर्वास कार्यों को विकास आयोजनों तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना।
- (घ) जहां पर विस्थापन, भूमि अर्जन के कारण होता है, वहां पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।

### 3. परिभाषाएँ—

इस नीति में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) 'अधिनियम' से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अभिप्रेत हैं।
- (ख) "प्रशासक" सरकार द्वारा उस परियोजना के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट या अपर जिलाधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी को पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (ग) "प्रभावित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए;
- (घ) "प्रभावित कुटुम्ब" के अन्तर्गत,—
- (i) ऐसा कोई कुटुम्ब है जिसकी भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का अर्जन किया गया है,
  - (ii) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसके स्थामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किन्तु ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य या ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है,
  - (iii) ऐसी अनुसूचित जनजातिया और अन्य पारम्परिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है,
  - (iv) ऐसा कोई कुटुम्ब है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक वनों या जलराशियों पर निर्भर रहा है और इसके अन्तर्गत वन उपज बटोरने वाले, आखेटक मत्स्यक जनसमूह और केवट भी हैं और ऐसी जीविका भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित हुयी है,

- (v) ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी योजनाओं में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है।
- (vi) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है;
- (ङ) “कृषि भूमि” से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है
- कृषि या उद्यान कृषि;
  - दुर्घ उद्योग, कुवकुट पालन उद्योग, मत्स्य-पालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नसरी में उगने वाली औषधीय जड़ी-बूटियों।
  - फसलों, वृक्षों, घास या उद्यान उत्पाद; और
  - पशुओं के चारागाह के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है।
- (घ) “समुचित सरकार” से—
- किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार,
- परन्तु किसी जिले के जिलाधिकारी को उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के सम्बन्ध में समुचित सरकार समझा जाएगा,
- (छ) “कलैवटर” से राजस्व जिले का कलैवटर (जिलाधिकारी) अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलैवटर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहीत कोई अधिकारी भी समिलित है;
- (ज) “आयुक्त” राज्य सरकार प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये उस सरकार के आयुक्त या सचिव की पवित्र के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जिसे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त कहा जायेगा।
- (झ) “अर्जन की लागत” के अन्तर्गत
- प्रतिकर की रकम जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर सदेय व्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुम्बों को सदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है।

- (ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदर्भ किया जाने वाला डेमरेज;
- (iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुम्बों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत,
- (vi) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में आवसरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत,
- (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा—अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत,
- (vi) इसके अन्तर्गत—
  - (क) भूमि जिसके अन्तर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो।
  - (ख) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों के जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च,
- (vii) “सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन” करने का खर्च,

- (अ) “विस्थापित कुटुम्ब” से ऐसा कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है,
- (ट) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में “कार्य करने के लिए हकदार” के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जायेंगे, अर्थात्—
  - (i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक जिस तक लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निशक्तता से ग्रस्त न होता,
  - (ii) अवयस्कों के सरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबन्धक, उसी सीमा तक, जिस तक अवयस्क पागल या अन्य विकृतचित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निशक्तता से ग्रस्त न होते;

परन्तु सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32 के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी मामले में वादमित्र द्वारा या सरक्षक द्वारा किसी जिलाधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

- (३) “कुटुम्ब” के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क सतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहने हैं:
- परन्तु विधवाओं और विवाह विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुम्बों द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक कुटुम्ब माना जायेगा;
- स्पष्टीकरण किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा सतान या आश्रितों हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक कुटुम्ब माना जायेगा,
- ऐसा प्रतिवार जो पद्धायत रजिस्टर भाग—२ के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया हो;
- (४) “भू—धृति” से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अधिभारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है;
- (५) “भूमि” के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले लाभ और भूबद्ध धीजें या मूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई धीजें आती हैं,
- (६) “भूमिहीन”से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे,—
- तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए, या
  - उपखण्ड (१) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में ऐसा भूमिहीन जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय,
- (७) “भू—स्वामी” के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,—
- जिसका नाम सम्बन्धित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है, या
  - जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिये गये हैं; या
  - जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अन्तर्गत समनुदेशित भूमि भी है, वनाधिकार दिये जाने का हकदार है, या
  - जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है
- (८) “बाजार मूल्य” से अधिनियम की धारा २६ के अनुसार अवधारित भूमि का मूल्य अभिप्रेत है,
- (९) “अधिसूचना” से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के साजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा,
- (१०) “पट्टा” का यही अर्थ होगा जो उसका सुसगत केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गये नियमों का विनियमों के अधीन दिया गया है,

- (न) "हितबद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है—
- (i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन मद्दे दिये जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं;
  - (ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारम्परिक वन निवासी, जिन्होंने 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अधीन किन्हीं भी वन्य अधिकारों को खो दिया है,
  - (iii) भूमि पर प्रभाव छालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति,
  - (iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृति अधिकार रखने वाले व्यक्ति जिनके अंतर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं, और
  - (v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;
- (प) "पुनर्वर्वस्थापन क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां प्रभावित कुदुम्बों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्वर्वस्थापित किया जाता है,
- (फ) "छोटा कृषक (लिमु कृषक)" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जो दो एकड़ तक की असिच्चित भूमि धारण करता है या एक एकड़ तक की सिचित भूमि धारण करता है किन्तु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है
- (ब) "सीमांत कृषक" से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है जिसके पास एक एकड़ तक की असिच्चित भू-धृति है या आधे एकड़ तक की सिचित भू-धृति है
- (भ) "पात्रता" पुनर्वास लाभों के लिए प्रभावित परिवारों की पात्रता अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(1) की अधिसूचना की तिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी,
- (म) "बेनाप धारक" से वह परिवार अभिप्रेत है जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तिथि के पूर्ववर्ती 3 वर्ष अथवा उससे पूर्व से बेनाप भूमिधर काबिज है तथा जिला प्रशासन से सत्यापित हो-
- (य) "अपेक्षक निकाय" से ऐसी कपनी निगमित निकाय, संस्था या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए समुचित सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना है और इसके अंतर्गत ऐसी समुचित सरकार भी है यदि भूमि का, ऐसी सरकार के अपने स्वय के उपयोग के लिए या ऐसी भूमि का, लोक प्रयोजन के लिए, बाद में यथास्थिति, किसी कपनी, निगमित निकाय, संस्था या किसी अन्य संगठन को पटटे, अनुज्ञाति के अधीन या भूमि अंतरण करने के किसी अन्य ढंग के माध्यम से अंतरण किए जाने के लिए, अर्जन किया जाता है।

- (યક) "વિકસિત કૃષિ/આવાસીય ભૂખણ્ડ" સે એસે ભૂખણ્ડ અભિપ્રેત હૈ જો સમતલીકરણ વ ડોલબન્ડી કર કૃષિ/આવાસ હેતુ ઉપયુક્ત હો। જિસમે સમ્પર્ક માર્ગ સે આવગમન સમ્ભવ હો એવ સિચાઈ સુવિધા/પેયજલ સુવિધા કી ઉપલબ્ધતા એવ ક્ષેત્ર મેં બિજલી વ્યવસ્થા હૃત્યાદિ હો।
- (યખ) "પરિયોજના" સે એસી કોઈ પરિયોજના અભિપ્રેત હૈ જિસકે લિએ ભૂમિ કા પ્રભાવિત વ્યક્તિ કી સર્વા કો વિચાર મેં લિએ બિના, અર્જન કિયા જા રહા હૈ।
- (યગ) "લોક પ્રયોજન" સે અધિનિયમ કી ધારા 2 કી ઉપધારા (1) કે અધીન વિનિર્દિષ્ટ કિયાક્રલાપ અભિપ્રેત હૈનું।

**નોટ-** ઉદ્યત પરિયાણો કે અતિરિક્ત અન્ય પરિયાણો કો ભૂમિ અર્જન, પુનર્વાસન ઔર પુનર્વિવસ્થાપન મેં ઉચ્ચિત પ્રતિકર ઔર પારદર્શિતા અધિકાર અધિનિયમ, 2013 કે અનુસાર લિયા જાયેગા।

**4. કટ ઓફ ડેટ-** અધિનિયમ કી ધારા 11 કી ઉપધારા(1) કે અધીન જારી અધિસૂચના કી તિથિ કો હી કટ ઓફ ડેટ માના જાએગા।

**5. ભૂમિ કે બાજાર મૂલ્ય કા અવધારણ-**

ભૂમિ કે બાજાર મૂલ્ય કા અવધારણ અધિનિયમ કી ધારા 28 સે 30 કે પ્રાવિધાનાનુસાર કિયા જાયેગા।

**6. ઢૂબ ક્ષેત્ર કા આકલન-**

પ્રભાવિત ઢૂબ ક્ષેત્ર કા આકલન જાતાશાય કે એફ૦આર૦એલ૦ ૯૮૦૦ મીટર સે ૦૩ મીટર ઊપર તક અર્થાત् ૯૮૩.૦ મી૦ આર૦એલ૦ તક આને વાલી ભૂમિ એવ ભવનો કા વિસ્થાપન કિયા જાયેગા।

**7. પ્રભાવિત પરિચારોં કે લિયે પુનર્વાસ તથા પુનર્વિવસ્થાપન લાભ-**

દિનાંક 08.09.2022 કો મુખ્ય સચિવ મહોદય કી અધ્યક્ષતા મેં આહૂત બૈઠક એવ દિનાંક 05.11.2020 કો આયુક્ત, ગઢવાલ મણ્ડળ મેં સમ્પન્ન સમન્વય સમિતિ કી બૈઠક મેં લિયે ગયે નિર્ણય કે અનુસાર :-

**7.1 પૂર્ણ પ્રમાણિત-**

એસે પ્રભાવિત ખાતેદાર જિનકી 50% યા 50% સે અધિક ભૂમિ પરિયોજના સે પ્રભાવિત હોગી/પરિયોજના હેતુ અધિગ્રહિત કી જાએગી, પૂર્ણ પ્રભાવિત કી શ્રેણી મેં આયેગો

**7.2 આંશિક પ્રમાણિત-**

એસે પ્રભાવિત ખાતેદાર જિનકી 50% સે કમ ભૂમિ પરિયોજના સે પ્રભાવિત હોગી/પરિયોજના હેતુ અધિગ્રહિત કી જાએગી, આંશિક પ્રભાવિત કી શ્રેણી મેં આયેંગો।

**7.3 ભૂમિ અધિગ્રહણ કા પ્રતિકર-**

(િ) પૂર્ણ પ્રભાવિત ખાતેધારકોં કો અધિગ્રહિત ભૂમિ કે એવજ મેં આધા (0.5) એકલ વિકસિત કૃષિ ભૂખણ્ડ એવ 200 વર્ગ મી૦ વિકસિત આવાસીય ભૂખણ્ડ કા

आवटन किया जाएगा। यदि कोई ऐसा परिवार भूमि नहीं लेना चाहता तो पूर्ण प्रभावित को अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित भूमि का नकद प्रतिकर दिया जायेगा।

ऐसे पूर्ण प्रभावित भूस्वामी जिनकी आधा (0.5) एकड़ से अधिक भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित होगी, ऐसे भूस्वामियों को आधा (0.5) एकड़ की सीमा से अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर पुनर्वास नीति के बिन्दु स० ७.३(ii)(क) के अनुसार दिया जायेगा।

ऐसे पूर्ण प्रभावित भूस्वामी जिनकी अधिग्रहित भूमि आधा (0.5) एकड़ की सीमा से कम है, उन्हें भी आधा (0.5) एकड़ भूमि आवटित की जायेगी एवं उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

- (ii) आशिक प्रभावित खातेधारकों को अधिग्रहित भूमि के ऐवज में प्रतिकर निम्नानुसार देय होगा—

(क) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर के मुगतान के प्रयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से अधिग्रहित भूमि की लागत का अवधारण जिलाधिकारी द्वारा विनिश्चित दरों के आधार पर किया जायेगा भूमि की दरें बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर जो भी अधिकतम होगा, से गणना की जायेगी। अधिनियम की धारा 26 की उपधारा(1) के मानदण्डों के अनुसार भूमि एवं भूमि से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की आस्तियाँ हेतु बाजार मूल्य का गुणक कारक दो (2.00) होगा। भूमि का अन्तिम अधिनिर्णय, बाजार मूल्य को कारक दो (2.00) से गुणा कर प्राप्त गुणनफल एवं उस पर 100 प्रतिशत तोषण के योग के बराबर होगा।

### भूमि-प्रतिकर की दर

(अ) भूमि की दर	=	बाजार मूल्य
(ब) ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वे कारक जिनके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाना है	=	02
(स) तोषण (सोलेशियम)	=	क्र०स० (अ) के सामने वार्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत-प्रतिशत के समतुल्य, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्र०स० (ब) के सामने विनिष्ट कारक से गुणित किया जायेगा
	=	बाजार मूल्य X 02
अतः भूमि प्रतिकर की दर	=	(अ X ब ) + स
	=	बाजार मूल्य X 04

(ख) अवयस्क खातेदार होने के दशा में खतौनी के कॉलम 2 तथा 7 से 12 में अवयस्क खातेधारकों की भूमि के मुआवजा की धनराशि अवयस्क खातेदार को एफ०डी० के रूप में दी जायेगी जिसे वह वयस्क होने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

- (ग) भूमि प्रतिकर की धनराशि का 10 प्रतिशत भुगतान भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् देय होगा।
- (ii) सौंग बाध पेयजल परियोजना के दूब क्षेत्र में निवासरत गैर भूमिधारक परिवार तथा भौतिक रूप से विस्थापित अथवा पूर्णत प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हो रहे हैं, से सम्बन्धित किसी भी लिंग का वयस्क व्यक्ति जिसे अधिनियम में पृथक प्रभावित परिवार परिभाषित किया गया है, को निम्न लाभ देय होगे-
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) विशिष्टियों के अनुरूप 50 वर्गमीटर आकाश के भूखण्ड पर निर्मित आवास या प्रभावित परिवार द्वारा भूखण्ड और/या आवास का विकल्प नहीं लिये जाने की दशा में उक्त के समतुल्य नकद प्रतिकर का विकल्प होगा प्रतिकर भुगतान के समय उपलब्ध बर्तमान मूल्य सूचकांक/अद्यतन सर्किल दरें लागू होगी
  - पंजीकरण शुल्क/स्टॉम्प फ्लूटी परियोजना द्वारा देय होगी।
  - प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगनों से मुक्त होगी

#### 7.4 स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार ]

- i. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिये संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- ii. प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिये भूमि सभी विलंगनों से मुक्त होगी।
- iii. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

#### 7.5 गृह संरचनाओं (आवास, दुकानों एवं पशुबाड़ा आदि) के लिये प्रतिपूर्ति (अधिनियम की पहली अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 व 5 के अनुसार)

अर्जन किये जाने वाले गृह संरचनाओं (आवास, दुकानों एवं पशुबाड़ा आदि) हेतु प्रतिपूर्ति की राशि का आकलन अधिग्रहण के समय लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा तथा इस मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) राशि के रूप में दी जायेगी।

#### 7.6 पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति (अधिनियम की पहली अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 व 5 के अनुसार)

पात्र भूस्वामी परिवारों को पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित भार्गदर्शी सिद्धान्तों और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य प्राधिकारियों/बागवानी विभाग/वन विभाग द्वारा दिये गये मूल्यांकन के अनुसार किया जायेगा तथा इस मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) राशि के रूप में दी जायेगी।

**7.7 वार्षिकी या नियोजन का विकल्प (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार)**

प्रति प्रभावित कुटुम्ब को ०६ लाख रुपए का एक मुश्त सदाय देय होगा।

**7.8 विस्थापित कुटुम्ब के लिए ०१ वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या ५ के अनुसार)**

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनियम की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रुपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जायेगा।

इस रकम के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किये गये अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोग ५० हजार रुपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगे।

**7.9 विस्थापित कुटुम्ब के लिए परिवहन खर्च (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या ६ के अनुसार)**

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जो विस्थापित हुआ है, कुटुम्ब भवन सामग्री घरेलू सामग्री और पशुओं को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में ५० हजार रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।

**7.10 पशुबाज़ा / छोटी दुकान खर्च (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या ७ के अनुसार)**

पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाज़ा या छोटी दुकान के निर्माण के लिये, एक मुश्त ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम २५ हजार रुपए की सीमा के अधीन विनिर्दिष्ट की जायें।

**7.11 कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कर्तिपय अन्य को एक मुश्त अनुदान (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या ८ के अनुसार)**

किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्था ढाँचा है और जिसे भूमि के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक मुश्त वित्तीय सहायता पायेगा, जो न्यूनतम २५ हजार रुपए की सीमा के अधीन रहते हुये विनिर्दिष्ट की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे छोटे दुकानदार जिनकी दुकान गैर सरकारी/सरकारी भूमि पर निर्मित है उन्हें समन्वय समिति द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देय होगा।

**7.12 एक मुश्त पुनर्वस्थापन भत्ता (अधिनियम की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या १० के अनुसार)**

प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल ₹० ५०,०००/- का एक मुश्त 'पुनर्वस्थापन भत्ता' दिया जायेगा।

### 7.13 बेनाप भूमि धारक / कब्जाधारक अथवा सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं के लिये प्रतिपूर्ति—

- (i) बेनाप भूमि पर काबिज कब्जाधारकों का सत्यापन धारा 11(1) की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की तिथि को आधार (अधिनियम की धारा ३ ग में प्रभावित कुटुम्ब की परिभाषा के अनुसार) मानते हुए किया जायेगा।
- (ii) बेनाप भूमि धारक / कब्जाधारक अथवा सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं के लिए निजी आवासीय/व्यवसायिक तथा अन्य परिसम्पत्तियों की हानि वाले बेनाप भूमि धारक को संरचना का लोक निर्माण विभाग (लो०निठिय०) के कुर्सी क्षेत्रफल की दरों के अनुसार आकलित मूल्य देय होगा।
- (iii) प्रभावित हुई संरचना तथा अन्य परिसम्पत्ति की सामग्री रक्षित करने का अधिकार होगा।

### 7.14 अन्य लाभ—

यथासम्बव परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को परियोजना निर्माण उपरान्त संचालित होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में प्राथमिकता दी जायेगी।

### ८. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुपरिधि —

- १ भूमि का कोई भी अर्जन, यथासंभव, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा।
- २ यदि ऐसा अर्जन होता है तो ऐसा केवल साध्य अंतिम अवलम्ब के रूप में किया जाएगा।
३. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन या अन्य सकारात्मक की दशा में भारत का सविधान की पाचवी अनुसूची के अधीन के अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति, सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों या स्वशासी जिला परिषदों की पूर्व सहमति ऐसे क्षेत्रों में भूमि अर्जन के, जिनके अन्तर्गत अत्यावश्यकता की दशा में अर्जन भी है, सभी मामलों में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने के पूर्व समुचित स्तर पर अभिप्राप्त की जाएगी।

परन्तु पंचायतों और स्वशासी जिला परिषदों की सहमति उन मामलों में अभिप्राप्त की जाएगी। जहां ग्राम सभा अस्तित्व में नहीं है या उसका गठन नहीं किया गया है।

- ४ किसी अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि के अर्जन को अतर्वलित करने वाली ऐसी किसी परियोजना की दशा में, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन अन्तर्वलित है, एक विकास योजना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उनमें भूमि संबंधी उन अधिकारों का, जो शोध्य है किन्तु जिनका परिनिर्धारण नहीं किया गया है, परिनिर्धारण करने तथा भूमि अर्जन सहित एक विशेष अभियान चलाकर अन्यसकारित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अनुसूचित जातियों

के हक्कों को बहाल करने सबधी प्रक्रिया के बौरे अधिकथित करते हुए, तैयार की जाएगी।

5. विकास योजना में गैरवन्ध भूमि पर पाच वर्ष की अवधि के भीतर वैकल्पिक ईंधन, वारे और गैरकाष्ठ वन्य उपज ससाधनों का विकास करने सबधी एक ऐसा कार्यक्रम भी होगा, जो जनजातीय समुदायों और साथ ही अनुसूचित जातियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

6. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भूमि का अर्जन किए जाने की दशा में, शोध्य प्रतिकर की कम से कम एक-तिहाई रकम का संदाय प्रभावित कुटुम्बों को प्रारम्भ में ही पहली किस्त के रूप में किया जाएगा और शेष रकम का संदाय भूमि का कब्जा ग्रहण किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

7. ऐसे पुनर्वासित क्षेत्रों को जिनमें मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं उस सीमा तक, जो समुचित सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, सामुदायिक और सामाजिक समूहों के लिए निशुल्क भूमि मिलेगी।

8. जनजातीय लोगों की भूमि या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमियों का तत्समय प्रवृत्त विधियों और विनियमों की अवहेलना करके किया गया कोई अन्यसंक्रामण अकृत और शून्य माना जाएगा और ऐसी भूमियों के अर्जन की दशा में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सबधी फायदे मूल जनजातीय भू-स्वामियों अथवा अनुसूचित जाति से संबद्ध भू-स्वामियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

9. प्रभावित अनुसूचित जनजातियों अन्य पारंपरिक वन्य निवासियों और अनुसूचित जातियों को जिनको प्रभावित क्षेत्र में नदी या तालाब या बाध में मछली पकड़ने के अधिकार प्राप्त है, सियाई या जल-विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार दिए जाएंगे।

10. जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रभावित कुटुम्बों को जिले के बाहर पुनर्वासित किया जाता है वहाँ उन्हें पचास हजार रुपए की एक मुश्त हकदारी के साथ अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन फायदे सदत्त किए जाएंगे जिन्हे वे धनीय रूप में पाने के हकदार होंगे,

## **9. आरक्षण और अन्य फायदे (Reservation and other benefits)**

1. वे सभी फायदे, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित क्षेत्रों में आरक्षण सबधी उपलब्ध फायदे भी हैं, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में भी मिलते रहेंगे।

2. जब कभी अनुसूचित जनजातियों से सबद्ध प्रभावित कुटुंबों को, जो भारत का संविधान की पाचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्वासित किया जाता है, तो उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपयोग किए जा रहे सभी कानूनी रक्षोपाय, हकदारियाँ और फायदे उन क्षेत्रों में सी जहा उन्हें पुनर्वासित किया जा है, इस बात पर विचार किए बिना कि पुनर्वासस्थापित क्षेत्र उक्त पाचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र या उक्त छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र है या नहीं प्रदान किए जाते रहेंगे।

3. जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन सामुदायिक अधिकारों का परिनिर्धारण किया जा चुका है वहां उनको धनीय राशि में परिमाणित किया जाएगा और ऐसे सबद्ध व्यष्टिक को, जिसको भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया गया है, ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में उसका संदाय किया जाएगा।

#### **10. समन्वय समिति (Co-ordination committee).**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन तथा पुनर्वास हेतु शासनादेश सं० 1942(1)/II(2)/2020-04(11)/2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के द्वारा समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य प्रभावित ग्रामीणों की पुनर्वास से सबमित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए समय-समय पर शासन को अवगत करना है। जिससे शासन द्वारा सम्बन्धित समस्याओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

#### **11. उच्च स्तरीय समिति के निर्णय अधिकार (Decision Powers of High Power Committee)**

पुनर्वास नीति लागू होने के उपरान्त नीति की व्यवहारिक कठिनाइयों या प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित किसी अन्य विन्दु के सम्बन्ध में निर्णय, जो कि इस पुनर्वास नीति में आच्छादित नहीं हो रहे हैं, पर निर्णय लेने का अधिकार शासन द्वारा सौंग बाध्य पेयजल परियोजना हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति (High Power Committee) को होगा।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,  
सचिव।

# Draft Policy for Rehabilitation and Resettlement of Song Dam Drinking Water Project

(As per the provisions laid in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)

**Irrigation Department, Uttarakhand**

## **1. Introduction**

The proposed Song Dam Drinking Water project is of utmost importance for the future drinking water supply of Dehradun city. The project shall ensure the supply of 150 MLD (1.75 cumecs) drinking water via gravity medium to Dehradun city and its suburban areas. It shall benefit 10 lac population till year 2051.

At present, the drinking water system of Dehradun city relies heavily on tube wells, it is the necessity to exploit other surface water sources in future, so that a sustainable plan of water supply can be prepared and balance can be struck between surface and groundwater sources. Construction of the project will result in a progressive reduction in the number of tube wells required to meet future demand which in turn will reduce the cost of construction, electricity consumption and operation & maintenance of tube wells. Pounding and reduced exploitation of ground water sources will also result in elevated ground water levels.

Song Dam Drinking Water Project is proposed on the river Song (longitude 78°11'30" E and latitude 30°18'08" N) near village Sondhana on the border of Dehradun and Tehri Garhwal district, at a distance of about 25 km from Dehradun city. Project proposes the construction of a 130.60 m (from the deepest foundation level) high.

03 villages namely Paled (Dehradun), Ragadgaon (Tehri Garhwal) & Ghurshalgaoon (Tehri Garhwal) shall be affected by the submergence area, and Sondhana (Tehri Garhwal) village shall be acquired for construction of quarries, batching plant and mixing plant. Thus, a total of 04 villages will be affected by the project.

This rehabilitation policy shall apply to the population affected by the project and has been drafted as per the provisions laid in the Right to Fair Compensation & Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013.

## **2. Objectives of Rehabilitation Policy**

**2.1. The objectives of the Rehabilitation Policy for the affected families of the Song Dam project are as follows:-**

- (a) To promote, as far as possible, alternatives to do minimal displacement, no displacement or least displacement.
- (b) To ensure an adequate rehabilitation package with the active participation of the affected persons and to ensure speedy implementation of the rehabilitation process.
- (c) To ensure careful and sensitive action concerning the protection and treatment of the rights and remedies of the weaker sections of the society, especially the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
- (d) To make joint efforts to provide a better standard of living to the affected families.
- (e) To integrate rehabilitation work with the development planning and implementation process.
- (f) To establish cordial relations between the acquiring body and the affected families through cooperation where displacement is caused by land acquisition.

### **3. Definitions**

**In this policy, unless the context otherwise requires—**

- (a) “Act” means The Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
- (b) ‘Administrator’ shall be appointed by the State Government not less than a Joint Magistrate or an Additional District Magistrate to be the Rehabilitation and Resettlement Administrator for that project.
- (c) ‘affected area’ means such area as may be notified by the appropriate Government for the purposes of land acquisition.
- (d) ‘affected family’ includes,—
  - (i) any family whose land or other immovable property has been acquired,
  - (ii) any family which does not own any land, but any member of such family or members of such agricultural labour, tenant including tenant in any form of enjoyment right, sharecropper or artisan or he/ she who are working in the affected area for three years before the acquisition of the land, whose main source of livelihood has been affected by the acquisition of the land;
  - (iii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 due to acquisition of land,
  - (iv) any family whose main source of subsistence, for three years before the acquisition of the land, has been dependent on forests or water bodies and includes forest produce gatherers, hunters, fishermen and boatmen and such subsistence is dependent on the acquisition of land, the cause is affected.
  - (v) any member of a family to whom land has been entrusted by the State Government or the Central Government under any of its schemes and such land is subject to acquisition
  - (vi) any family which has been residing in urban areas for three or more years preceding the acquisition of the land or whose main source of livelihood was the acquisition of such land for three years before the acquisition of the land, is affected by,
- (e) ‘agricultural land’ means land used for—
  - (i) agriculture or horticulture,
  - (ii) the dairy industry, poultry industry, fisheries, sericulture, seed cultivation, livestock breeding or nursery-growing medicinal herbs,
  - (iii) growing crops, trees, grasses or garden products; and
  - (iv) land used for grazing cattle.
- (f) ‘appropriate Government’ means—
  - concerning the acquisition of land within the territory of a State, the State Government;
  - Provided that the District Magistrate of a district shall be deemed to be the appropriate Government concerning any

public purpose in that district for an area not exceeding such area as may be notified by the appropriate Government,

- (g) 'Collector' means the Collector (District Magistrate) of a revenue district, and includes any officer specially designated by the appropriate Government to perform the functions of a Collector under this Act;
- (h) 'Commissioner' The State Government shall appoint an officer of the rank of Commissioner or Secretary to that Government to be called the Rehabilitation and Resettlement Commissioner for the rehabilitation and resettlement of the affected families.
- (i) - 'cost of acquisition' includes—
  - (i) the amount of compensation, including any enhanced compensation and interest payable thereon by the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority or the tribunal ordered by the Court and any other amount determined by such authority or court as payable to the affected families,
  - (ii) the demurrage to be paid for damage caused to land and standing crops in the process of acquisition;
  - (iii) the cost of acquisition of land and building for the settlement of displaced and adversely affected families,
  - (iv) the cost of development of infrastructure and amenities in resettlement areas,
  - (v) the cost of rehabilitation and resettlement as determined under the provisions of this Act;
  - (vi) it includes—
    - (a) administrative expenses for the acquisition of land, including both the land at the project site and the land outside the project area, not exceeding the such percentage of the cost of compensation as may be specified by the appropriate Government;
    - (b) the administrative expenses for the rehabilitation and resettlement of the owners of the land and other affected families whose land has been acquired or is proposed to be acquired or other families affected by such acquisition;
  - (vii) the cost of conducting "social impact assessment studies".
- (j) 'displaced family' means any family which is to be resited and resettled from the area affected by land acquisition to the resettlement area;
- (k) 'entitled to act', concerning any person, shall include the following persons, namely—
  - (i) a trustee for other persons interested as the beneficiary by reference to any such case, to the extent to which the person interested as beneficiary could have acted if he had not suffered from a disability;
  - (ii) the guardian of minors and the custodian or manager for the lunatic, to the same extent to which the minor, lunatic or another person of unsound mind himself could have acted if he had not suffered from a disability

Provided that the provisions of Order 32 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall, in the case of persons interested in the proceedings under this Act, appear before any District Magistrate or authority by the plaintiff or by the guardian, as may be necessary, changes will be applicable;

- (l) 'family' includes any such person, his dependent wife or husband, minor children, minor brothers and minor sisters; Provided that widows and divorced women and women deserted by famines shall be treated as separate families;  
Explanation- An adult person of either sex, whether or not having a wife or husband or children or dependents, shall be treated as a separate family for this Act;  
The such family has been recorded under Panchayat Register Part-II;
- (m) 'holding of Land' means the total amount of land held by any person as owner, occupier or overlord or otherwise;
- (n) 'land' includes profits arising out of land and things attached to the ground or things permanently attached to anything attached to the ground,
- (o) 'landless' means a person or class of persons who,—
  - (i) to be treated as or specified under any State law for the time being in force; or
  - (ii) in the case of a landless person not to be specified under sub-section (i), such landless as may be specified by the appropriate Government
- (p) 'land owner' includes any person—
  - (i) whose name is recorded in the records of the authority concerned as the owner of the land or building or any part thereof; or
  - (ii) who has been granted lease rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or under any other law for the time being in force; or
  - (iii) who is entitled under any law of the State to be given forest rights on land including assigned land, or
  - (iv) declared as such by any order of the Court or the Authority.
- (q) 'market value' means the value of land determined according to section 26 of the, Act;
- (r) 'notification' means a notification published in the Gazette of India or the Gazette of a State, as the case may be, and the expression "to notify" shall be construed accordingly,
- (s) 'lease' shall have the meaning assigned to it under the relevant Central or State Acts or regulations made there under;
- (t) 'person interested' means—
  - (i) all persons who claim an interest in compensation to be paid on account of the acquisition of land under this Act;
  - (ii) the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any forest rights under the "Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006,"
  - (iii) any person interested in any easement affecting the land,

- (iv) persons having tenancy rights under the relevant State laws, including sharecroppers in crops, by whatever name called, and
- (v) any person who is likely to be prejudicially affected by his main source of livelihood,
- (vi) 'resettlement area' means an area assigned to the affected families, who have been displaced as a result of the acquisition of land, to be resettled by the appropriate Government;
- (vii) 'small farmer' means a cultivator who holds unirrigated land up to two acres or irrigated land up to one acre, but holds more than the holding of a marginal farmer;
- (viii) 'marginal farmer' means a cultivator who has irrigated land holding up to one acre or irrigated land holding up to half an acre;
- (ix) 'eligibility' the eligibility of the affected families for rehabilitation benefits shall be determined on the date of notification of sub section(1) of Section 11 of the Act.
- (y) 'benap holder' is the family which owns benap bhumidhar for 3 years on or before the date of notification of the affected area and is verified by the district administration.
- (z) 'requiring body' means a company, body corporate, institution or any other organization or person for which land is to be acquired by the appropriate Government and includes such appropriate Government if the land is owned by such Government, of such land for its use or a public purpose, subsequently to any company, body corporate, institution or any other organization, as the case may be, under the lease, license or through any other mode of transfer of land To be transferred, the acquisition is made.
- (za) 'developed agricultural/residential plot' means such a plot which is suitable for agriculture/housing by leveling and mobilization in which transportation is possible through contact road and availability of irrigation facility/drinking water facility and electricity system in the area etc.
- (zb) 'project' means any project for which land is being acquired irrespective of the number of persons affected.
- (zc) 'public purpose' means the activities specified under sub-section (1) of section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

*Note: In addition to the above definitions other definitions shall be considered as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013*

#### **4. Cut-off date**

- (a) The date of notification issued under sub section(1) of Section 11 of the Act, shall be considered the cut-off date

## **5. Determination of market value of the land**

The market value of the land shall be determined as per the provisions of sections 26 to 30 of the Act.

## **6. Assessment of submergence area**

Land and infrastructures up to the reduced level (R.L.) of 983.00 m i.e., 3 meters above Full Reservoir Level (F.R.L.) of 980.00 m shall be displaced.

## **7. Rehabilitation and resettlement benefits for the affected families**

As per the decisions reached in the meeting of the Coordination Committee held under the chairmanship of Commissioner, Garhwal on 05/11/2020 and on 08/09/2022 under Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand:-

### **7.1. Fully Affected-**

Such affected account holders whose 50 per cent or more than 50 per cent of the land be affected by the project will be acquired for the project, will come under the category of fully affected.

### **7.2. Partially Affected-**

Such affected account holders whose less than 50% of the land be affected by the project, will be acquired for the project, will come in the category of partially affected.

### **7.3. Compensation for land acquisition-**

- (i) Half (0.5) acre developed agricultural plot and 200 square meters of developed residential plot will be allotted to the fully affected family. If any, such family opts not to take the land, then the fully affected shall get cash compensation for the acquired land as per Act.

Such wholly affected landowners with more than half (0.5) acre land being acquired for the project, such land owners will be given compensation for the acquired land over the limit of half (0.5) acre as per point no. 7.3 (ii)(a) as per this Policy.

Such fully affected landowners with land being acquired under the limit of half (0.5) acre, will also be allotted half (0.5) acre of land and no additional fee will be charged to them. If any, such family opts not to take the land, then the fully affected shall get cash compensation for the 0.5 acre land as per RFCTLARR Act 2013.

- (ii) Compensation for partially affected families shall be given as per below-
  - (a) According to the provisions of the Act, the cost of land acquired from any person for payment of compensation shall be

determined based on rates decided by the District Magistrate. The land rates shall be calculated from the market value or circle rate whichever is higher. According to the norms of sub section (1) of section 26 of the Act, the multiplying factor of two (2.00) will be applicable on the market value of the land and the assets attached to the land in the rural areas. The final award of the land will be equal to the product of multiplying the market value by factor two (2.00) and the sum of 100% of the market value as Solatum.

#### Land compensation rate

- (a) Rate of the land = Market value
- (b) Factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural areas = 2
- (c) Solatum (*Toshan*) - equal to 100% of the market value of the land mentioned against serial number (a), multiplied by the factor specified against serial number (b) for rural areas  
= market price x 02

#### Therefore, the rate of land compensation

$$\begin{aligned} &= (a \times b) + c \\ &= \text{Market value} \times 04 \end{aligned}$$

- (b) In the case of being a minor account holder, in columns 2 and 7 to 12 of *Khatauni*, the amount of compensation for the land of minor account holders will be given to the minor account holder in the form of FD, which he/she will be entitled to receive when he/she becomes an adult.
- (c) 10% of the amount of land compensation shall be payable after obtaining possession of the land.
- (iii) The non-titleholder family residing in the submergence area and physically displaced or adult of either gender belonging to fully affected families and defined as separate affected family as per Act shall be entitled to-
  - A constructed house on a 50 sqm plot area conforming to Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) specifications, or if plot and/or house is not opted by any affected family, equivalent cash compensation shall be payable. Available current price index updated circle rates shall apply during the time of payment of compensation.
  - Registration charges/stamp duty will be payable by the project.
  - The land for house allotted to the affected family shall be free from all encumbrances.

#### **7.4. Stamp Duty and Registration Fee**

(As per point no.11 of the Second Schedule to the Act)

1. The stamp duty and other fees payable for the registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the requiring body

- ii. The land for the house allotted to the affected families shall be free from all encumbrances
- iii. The land or house allotted may be in the joint names of both, the wife and the husband of the affected family

**7.5. Reimbursement for house structures (accommodation, shops and animal shed etc.)**

(As per points no. 4 and 5 of the First Schedule of the Act)

The amount of reimbursement for the house structures (housing, shops and animal shed etc.) to be acquired will be determined based on the rates of the Public Works Department at the time of acquisition and 100% of this value will be given in the form of a solatium amount.

**7.6. Reimbursement for the Trees**

(As per points no. 4 and 5 of the First Schedule of the Act)

Reimbursement for trees to the eligible landowner families will be given as per the guiding principles prescribed by the State Government, in accordance with the assessment carried out by the State Authorities/ Horticulture Department/ Forest Department, 100% Solatium amount on above assessed amount shall be provided.

**7.7. Option for annuity or employment**

(As per point no. 4 of the Second Schedule of the Act)

One-time payment of Rs. 5 lacs will be payable per affected family

**7.8. Subsistence grant for the displaced families for 1 year**

(As per point no. 5 of the second schedule of the Act)

Every affected family who has been displaced from the acquired land shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for one year from the date of the award.

In addition to this amount, people belonging to the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes displaced from the Scheduled Areas will get an amount equivalent to 50 thousand rupees.

**7.9. Transport Expenses for Displaced Families**

(As per point no. 6 of the Second Schedule of the Act)

One-time financial assistance of Rs 50,000 will be given to each affected family who has been displaced, as transportation expenses for taking the family, building materials, household materials and animals to another place

**7.10. Animal Farm / Small Shop Expenditure**

(As per point no. 7 of the Second Schedule of the Act)

Every affected family having cattle or a small shop shall receive financial assistance of such amount for the construction of an animal shelter or small shop, as the case may be, for such amount as may be specified subject to a minimum limit of Rs.25,000

**7.11. One-time grant to artisans, small traders and certain others**

(As per point no. 8 of the Second Schedule of the Act)

Every affected family of an artisan, small trader or self-employed person or such affected family-owned by non-agricultural land or commercial, industrial or institution structure in the affected area and who has been involuntarily displaced from the affected area because of the land, such amount One-time

financial assistance of Rs 25,000/-, which will be specified subject to a minimum ceiling of Rs.25 thousand. Apart from this, such small shopkeepers whose shop is built on non-government/government land will be given additional incentive allowance as decided by the coordination committee.

#### **7.12. One Time Resettlement Allowance**

(As per point no. 10 of the Second Schedule of the Act)

Each affected family will be given a one time 'Resettlement Allowance' of Rs.50,000/- only

#### **7.13. Compensation to Benap land holder/encroachers or structures built on government land-**

- (i) Encroachers on Benap Bhumi shall be identified from the date prior to 03 years before the date of notification (As per the definition of affected family laid out in section 3(c) of the Act).
- (ii) Benap Bhumi holder/Encroachers or title holder affected family losing residential/ commercial and other structures shall be compensated for infrastructures equivalent to amount calculated as per PWD - Works Department (PWD) plinth area rates.
- (iii) Right to salvage materials from the lost structures and other assets

#### **7.14. Other Benefits:-**

As far as possible, the villagers of the project affected area will be given priority in the commercial activities to be conducted after the construction of the project.

#### **8. Special provisions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes-**

1. As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas.
2. Where such acquisition does take place it shall be done only as a necessary last resort.
3. In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha or the Panchayats or the autonomous District Councils, at the appropriate level in Scheduled Areas under the Fifth Schedule to the Constitution as the case may be, shall be obtained, in all cases of land acquisition in such areas, including acquisition in case of urgency, before issue of a notification under this Act, or any other Central Act or a State Act for the time being in force.

Provided that the consent of the Panchayats or the Autonomous Districts Councils shall be obtained in cases where the Gram Sabha does not exist or has not been constituted.

4. In case of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes families, a Development Plan shall be prepared, in such form as may be prescribed, laying down the details of procedure for settling land rights due, but not settled and restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive together with land acquisition.

5. The Development Plan shall also contain a programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes.
6. In case of land being acquired from members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, at least one-third of the compensation amount due shall be paid to the affected families initially as first instalment and the rest shall be paid after taking over of the possession of the land.
7. The resettlement areas predominantly inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall get land, to such extent as may be decided by the appropriate Government free of cost for community and social gatherings.
8. Any alienation of tribal lands or lands belonging to members of the Scheduled Castes in disregard of the laws and regulations for the time being in force shall be treated as null and void, and in the case of acquisition of such lands, the rehabilitation and resettlement benefits shall be made available to the original tribal land owners or land owners belonging to the Scheduled Castes.
9. The affected Scheduled Tribes, other traditional forest dwellers and the Scheduled Castes having fishing rights in a river or pond or dam in the affected area shall be given fishing rights in the reservoir area of the irrigation or hydel projects.
10. Where the affected families belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are relocated outside of the district, then, they shall be paid an additional twenty-five per cent. rehabilitation and resettlement benefits to which they are entitled in monetary terms along with a onetime entitlement of fifty thousand rupees.

## **9. Reservation and Other Benefits**

1. All benefits, including the reservation benefits available to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the affected areas, shall continue in the resettlement area.
2. Whenever the affected families belonging to the Scheduled Tribes who are residing in the Scheduled Areas referred to in the fifth schedule or the tribal areas referred to in the Sixth Schedule to the Constitution, are relocated out of those areas, then, all the statutory safeguards, entitlements and benefits being enjoyed by them under this Act shall be extended to the area to which they are resettled regardless of whether the resettlement area is a Scheduled Area referred to in the said fifth schedule or a tribal area referred to in the said sixth schedule, or not.
3. Where the community rights have been settled under the provisions of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(2 of 2007) the same shall be quantified in monetary amount and be paid to the individual concerned who has been displaced due to the acquisition of land in proportion with his share in such community rights.

## **10. Coordination Committee**

For the implementation and rehabilitation involved in the project, a coordination committee has been constituted vide Uttarakhand Government mandate number 1942(1)/II(2)/2020-04(11)/2010, dated October 23, 2020. The purpose of the committee is to take cognizance of the grievances of the affected villagers and apprise

the government of the same, so that the government may decide on the grievances after due consideration.

### **11. Decision Powers of High Power Committee**

After the implementation of this policy, it shall be under the authority of High Power Committee (H P C.) constituted by government for Son Dam Drinking Water Project, to redress problems related to functioning of this policy or decide on matters regarding affected families which are not covered under this policy.

By Order

**HARI CHANDRA SEMWAL**  
*Secretary*

**गृह अनुभाग—१**

**विज्ञप्ति / पदोन्नति**

1५ नवम्बर, 2022 ई०

**संख्या 1201 / XX-1-2022-3(12) 2014—उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संदर्भ के पुलिस उपाधीकार, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लोडल-10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन धर्ष 2021-22 की रिकियाँ के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिहार डारा की गयी सरकु ते के आधार पर निम्नलिखित रथ यी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीकार कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

क्र.सं.	अधिकारी का नाम संक्षेपी
1	ऋषिबलभ चौमोला
2	संजय सिंह गव्याल
3	भास्कर साल शाह

2— उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीकार कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अधीन रहेगी।—

- 1) उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से ०२ वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, २००९ के नियम-२४ में प्रावधान है।
- 2) उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अध्यर्थियों के साथ कालातर में सुसगति नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 3) पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

- 4) उक्तवत् पदोन्नति मा० लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड में योजित् निर्देश याचिका संख्या 25/डीबी/2020 श्री सदीप नोगी, निर्देश याचिका संख्या 45/डीबी/2021 श्री प्रबोध कुमार घिलियाल संख्या 42/एनबी/डीबी/2021 श्री राकेश मेहरा निर्देश याचिका संख्या 66/एनबी/डीबी/2021 श्री मनीष जसवाल निर्देश याचिका संख्या 163/एसबी/डीबी/2022 श्री चंचल शर्मा बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित् रिट याचिका संख्या 1393(एस०बी०)/2020 नदीम अंतहर बनाम उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य मैं मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आशा से,

विजय कुमार,  
संघ सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुढ़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 03, 1944 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

गियम, कार्य-विधियाँ, आप्लाए, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों  
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL NOTIFICATION

November  
December 02, 2022

No. 359/XIV-a/37/Admin A/2009--Shri Sandip Kumar Tiwar, Principal Magistrate Juvenile  
Justice Board, Dehradun is hereby sanctioned Paternity leave for 16 days w.e.f. 31.10.2022 to 14.11.2022.

### NOTIFICATION

November  
December 02, 2022

No. 360/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms Kapana, Civil Judge (Jr Dv) Kashipur District Udhampur  
Nagar is hereby sanctioned Med.ca. leave for 87 days w.e.f. 25.07.2022 to 19.10.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

*Registrar (Inspection)*

NOTIFICATION

December 02, 2022

No. 361/UHC/Admin.A/2022--In supersession of Notification No. 356/UHC/Admin A/2022 dated 24.11.2022 Shri Dhananjay Chaturvedi Secretary (Law)-cum-L.R. Government of Uttarakhand is repatriated from his present posting with immediate effect and attached to the High Court at Nainital.

Sri Dhananjay Chaturvedi is directed to leave the charge of his present posting and to report to the High Court at Nainital immediately.

The nomination of Sri Narendra Dutt, District & Sessions Judge, Champi for the post of Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand stands withdrawn.

By Order of the Court

Sd/-

VIVEK BHARTI SHARMA

*Registrar General*

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY  
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 08, 2022

No. 1434/III-A-07/2022/SLSA--Ms. Shama Parveen, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned medical leave for a period of 23 days w.e.f. 12.11.2022 to 04.12.2022.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R K. KHULBEY,

*Member Secretary,**Uttarakhand State Legal Services  
Authority, Nainital*



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुद्रकी, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2022 ई० (पौष 03, 1944 शक समवत्)

भाग ४  
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

### सूचना

सर्वसामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र वालिद आली व उसका परिवार गेरे कहने सुनने में नहीं होने के कारण मैं और मेरा परिवार उससे पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद करते हैं एवं अपनी चल अचल सम्पत्ति से मी बेदखल करते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार के कृत्य, लेन-देन आदि के बैं स्वयं जिम्मेदार होंगे।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

मौरुम्मद हनीफ पुत्र इब्राहिम  
निवासी सुल्तानपुर आदमपुर, लक्ष्मण  
जिला हरिहार।

## કાર્યાલય નગર પંચાયત, પુરોલા (ઉત્તરકાશી)

### નગર પંચાયત પુરોલા, ઉત્તરકાશી—પ્રસ્તાવિત ઉપવિધિ

31 મે, 2022 ઈ0

पત્રાંક 162/નોંધું/2022-23-નગર પંચાયત અધિનિયમ 1916 કી થારા-299 (1) કે અધીન શક્તિઓ કે પ્રયોગ મેં નગર પંચાયત પુરોલા દ્વારા બનાએ ગણ નિર્બનિલિચિત્ર ઠોસ કચરા પ્રબળન કે લાએ ઠપવિધિઓ કો અપને કોન્નાથિકાર મેં નગર પંચાયત પુરોલા કે અધિવેશન દિનાંક 12 08 19 મેં પ્રસ્તાવ સં0 01 કે જાખ્યમ સે ર્યા ગયા એવં આપણી એવં સુદ્ધાર હેતુ વિશેષ સંકલપ સે પારિત હુઆ। જિસે જન સામાન્ય કે અવલોકન હેતુ પ્રકાશિત કર્યા જા રહા હૈ જિસ કિસી ભી ક્ષવિત કો કોઈ આપણિ યા સુદ્ધાર હો તો વહ અપણી આપણિ/સુદ્ધાર કો ઉક્ત ઉપ નિયમ કે અસ્વાર મેં પ્રકાશન કે 15 દિન કે ભીતર નગર પંચાયત કાર્યાલય મેં કિસી ભી કાર્ય દિવસ મેં સ્વતંત્ર 10 બજે સે સાથે 5 બજે તક પ્રસ્તુત કર સકતા હૈ, નિર્ધારિત અધિકિ કે ઉપરાંત કિસી ભી પ્રાપ્ત આપણિ/સુદ્ધાર પર કોઈ ભી વિચાર કિયા જાના સમય વહી હોણા.

અધ્યાય-187

#### **સામાન્ય**

##### **1. સંક્ષેપ્ત નામ ઔર લાગુ હોને કી તારીખ :**

(1) યે ઉપ-નિયમ - નગર પંચાયત પુરોલા, ઉત્તરકાશી ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબધન ઉપ-નિયમ, 2019 કહાલાએંगે।

(2) યે ઉપ-નિયમ નગર પંચાયત પુરોલા, ઉત્તરકાશી કે સરકારી મજટ ઉત્તરાખંડ મેં પ્રકાશિત હોને કી તારીખ સે પ્રભાવી હોણે

(3) નગરીય ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબધન ઉપવિધિ 2009, મજટ નોટિફિકેશન 16 જુલાઈ 2010 દ્વારા પ્રાચ્યપિત ઉપવિધિ નગર પંચાયત પુરોલા, ઉત્તરકાશી ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબધન ઉપ-નિયમ 2019 લાગુ હોને કી તિથી સે સ્વતંત્ર સમાપ્ત હો જાયેંગે

2. યે ઉપ-નિયમ નગર પંચાયત પુરોલા કી સીમાઓ કે ભીતર લાગુ હોણે

##### **3. પરિભાષાએ**

(1) જદુ તક કી સંદર્ભ સે અન્યથા અપેક્ષિત ન હો, ઇસ ઉપ નિયમો મેં લિખ્નાવિત પરિભાષાએ લાગુ હોને -

(અ) "બલ્ક ઉધાન ઔર બાળવાન કચરા" કા અર્થ હૈ ઉધાનો, બાળો આદિ સે ઉત્સર્જિત બલ્ક કચરા, જિસમે ઘાસ કસ્ટાન, ખર્પતવાર, કાર્બનયુક્ત કાણ્ઠ બ્રાઉન સામગ્રી જેસે પેડો કી છટાઈ સે ઉત્પન્ન કચરા, પેડો કી કટિંગ, ટહનિયા, લસ્કડી કી કતરન, ભૂસા, સ્ફૂર્તી પત્તિયા, પેડો કી છટાઈ આદિ સે ઉત્પન્ન ઠોસ કચરા જો દૈનિક જીવ અપઘટીય કચરે કે સંકલન મેં સમાયોજિત નહીં કિયા જા સકતા હૈ।

(અ) "બલ્ક કચરા ઉત્સર્જન કા અર્થ હૈ કી ઠોસ કચરા પ્રબધન નિયમ, 2016(જિસે બાદ મેં યથા એસ.ડબલ્યૂ.એમ નિયમ કહા જાએંગા) કે નિયમ 3(1) (૪) કે મતર્ગત પરિભાષિત બલ્ક કચરા ઉત્સર્જક ઔર સમ્બદ્ધ વાર્ડ નગર પંચાયત પુરોલા દ્વારા અપિસ્ચિત ઠોસ કચરા ઉત્સર્જક;

(ગ) "સંગ્રહ" કા અર્થ હૈ, કચરા ઉત્સર્જન કે સ્નોટ સે ઠોસ કચરે કો ઉઠાના ઔર સગ્રહણ બિનુઓ યા કિસી અન્ય સ્થળ તક પહુંચાના;

• (घ) "साक्षम प्राधिकरी" का अर्थ हैं नगर पंचायत पुरोला अधिकार, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) निर्माण एवं विष्टवंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विष्टवंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभ्रषित किया गया हैं

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती पुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के बिनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना है।

(छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (दलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे भालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संदर्भ केंद्र;

(ज) "कटेमराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) "सुपुर्टग्री" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्टग्री के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त ऐजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "फिल्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊजो चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है,

(ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संबह करना इन उप-नियमों के अलंगत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जनु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) "गदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गदगी उत्सर्जित करना डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह बिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो.

(इ) "स्कामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;

(ण) 'अधिभोगी/पटटेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पटटेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

- (प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्षूब अथवा फ़िल्डरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके इधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइव्ड इधन कहा जाता है।
- (फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरजन के लिए सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (अ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आदारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (म) "रीनेटरी लंकर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने उद्योग नालियों को साफ करने के लिये नगरों पंचायत / ऐजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (य) "शैद्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शैद्यूल;
- (र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा सम्बद्ध समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के लिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, तकि ठोस कचरा संग्रह ढुलाई, प्रोसेसिंग और निष्पातन सेवाओं की अधिक अपवा पूर्ण लागत कवर की जा सके;
- (ल) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/घृषकित/सरकारी ऐजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी शून्य या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;
- (२) यहाँ प्रयुक्त लेकिन परिभिरुद्ध न किए शब्दों और अविव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और नियमांश एवं विष्टंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में उल्कित होगा।

#### अध्याय -2

##### ठोस कचरे का स्वीत पर पृथक्करण और संग्रहण

###### 4. ठोस कचरे का स्वीत पर पृथक्करण और संग्रहण

- (i) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने काले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करे और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से नियमकित ३ वर्गों में किया जायेगा:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या ग्रीला कचरा

(ग) धरेलू जॉखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

- (ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे नियमकित ३ वर्गों में।

(क) गैर जैव अपघटीय या खुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़दानों में जोखिमपूर्ण कचरा जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायो-स आदि तैयार करना एवं पृथक्करण कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रासाकरण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित तुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एंजेसी को करेगा।

(ii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़दानों का रग इस प्रकार होगा -

हरा:- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:- गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए;

काली:- अरेतु औरिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के आगीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिल्डों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एंजेसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर झेल से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वाराबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिल्डों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एंजेसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां नगर पंचायत पुरोला के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिल्डों में संगृहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगे, जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एंजेसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, तकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एंजेसी को सौंपा जा सके।

(viii) सेमिट्री उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्परताधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मलिकों द्वारा प्रदान किए गए प्राइवेट अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से सल्वेचित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ैदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेट, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सद्बिजयां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ैदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कटेनर या बाहन को सौंपेगा।

(x) इदयान और बागवानी के कथरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जौखिमपूर्ण कंथरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए बाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या सञ्चय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यों और अवानी को छोड़ जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बाथों मेंिकल कचरा, ई-कचरा, जौखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचड़खानों और खाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मलिक/कठजाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशुपथ संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हों, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमरा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा बाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में भाजना निषेद्ध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/ब्राह्मण/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह बाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुरुदगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

### अध्याय-३

#### ठोस कचरा संग्रह

##### ५. ठोस कचरे का संग्रह निर्मांकित अनुसार किया जाएगा-

(i) नगर पंचायत के सभी द्वीपों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक

आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संघह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेलसइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः ६ बजे से ११ बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वर्णितियक क्षेत्रों में टुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः ७ बजे से दोपहर १२ बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएंगे।

(iv) सड़जी फल, फूल, भास पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमरा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(vi) फलों और सड़जी बाजारी, भास और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संवाहण एवं दुलाई की लागत में कभी भाले के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(vii) कटेजरी में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान शिक्षिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समृद्धि संरक्षण के लक्ष्य किया जाएगा,

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पस/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड ४ व उप-खंड(पअ) और (अ) के अन्तर्गत आगे बालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वारा से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पाटेंट होंगे। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित होने भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए सार्व योजनाएं और नगर पंचायत द्वारा या अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्द और बीआईएस मानचित्र में होंगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होंगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, भतिज बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत

અથવા અધિસૂચિત અધિકૃત કચરા સંગ્રહકર્તા દ્વારા પ્રત્યેક ગલી મેં એક કોડે લગાયા જાએगા જિસ પર પ્રાથમિક કચરા સંગ્રહ ઔર ઠુલાઈ વાહનોં કી સમય સારણી પ્રદર્શિત કી જાએગી,તાકી ક્ષેત્ર કે નિવાસી નિર્ધારિત સમય પર ઇસ સુવિધા કા લાભ ઉઠ સકે। એસી જાનકારી નગર પંચાયત કી વેબસાઇટ પર અપલોડ કી જાએગી।

(xii) તંગ ગલિયો મેં, જહાં ઑટો ટિપ્પર યા વાહન કી સેવાએ સંભવ ન હોય, વહા એક થ્રીલ્વીલર અથવા છોટે મોટરયુક્ત વાહન, સાઝ્યકિલ રિક્શા કામ પર લગાયા જાએગા,જો ઊપર સે હાઇડ્રોલિક તરીકે સે સંચલિત હૂપર કવરિંગ વ્યવસ્થા સે યુક્ત હોય ઔર ઉસમે ગીલે ઔર સૂખે કચરે કે લિએ અલગ અલગ દો કમ્પાર્ટમેન્ટ હોયાં, એસે વાહનો મેં હૂટર લગ હોયાં ઔર વહ મોબાઇલ ટ્રાસ્ફર સ્ટેશન કે અનુકૂળ હોયાં।

(xiii) અત્યંત ભીડ બાલે ઔર અધીક તગ ગલિયો વાલો લોગો મેં જહાં થ્રીલ્વીલર યા છોટે વાહન બી ન જા સકે વહાં સાઝ્યકિલ રિક્શા અથવા અન્ય પ્રકાર કે ઉપયુક્ત ઉપકરણ તૈનાત કિએ જાએગો।

(xiv) એસી છોટી, લંગ ઔર ભીડી ગલિયો/લેનોં મેં જહાં થ્રીલ્વીલર/રિક્શા આદિ કા સંચાલન સમય ન હો, એસે સ્થાનો પર બસ્ટિ/ગલી કે ઠોર પર ખાસ જગદ તથ કી જાએગી, જહાં કચરા સંગ્રહ વાહન ખડા ક્રિયા જા સકે ઔર વાહન કે હૈલપર કે પાસ એક સીટી હોયી ઔર વે સીટી બજાતે હુર ગલી મેં ઠોસ કચરા સંગ્રહણ કે લિએ વાહન કે આગમન કી ઘોષણા કરેંગે ઇસ તરફ કી સંગ્રહ પ્રણાલી કી સમય સારિણી નોટિસ કોડ પર લગાઈ જાએગી ઔર નગર પંચાયત કી વેબસાઇટ પર અપભોડુ કી જાએગી।

(xv) ઑટો ટિપ્પર, થ્રીલ્વીલર, રિક્શા ઔર સેવા મેં સંલગ્ન બિસી અન્ય તરહ કે વાહન કેવળ ધરો સે કચરા એકત્ર કરેંગે, ઔર અન્ય સ્ત્રોતો જેસે દલાદ, ખૂલે સ્પલ્લો, મૈદાન, ક્રૂંદાલોં ઔર નાલિયોં આદિ સે કચરા એકત્ર નહીં કરેંગે।

(xvi) નગર પંચાયત યા ઉસકે અધિસૂચિત અધિકૃત કચરા સંગ્રહતો પ્રાથમિક કચરા સંગ્રહણ કે લિએ ક્ષેત્ર કી સભી ગલિયો/લેનોં કો કવર કરને કે લિએ જિસ્ટેન્ડાર હોયોં।

#### આંયાચ-4

##### ઠોસ કચરે કા દ્વિતીયક સંગ્રહણ

###### 6. દ્વિતીયક સંગ્રહણ બિંડુઓ મેં ઠોસ કચરે કા સંગ્રહણ નિર્માનિત અનુસાર કરિયા જાએગા

(i) ધરો મેં એકત્ર કરિયા ગયા પૃથ્યક ઠોસ કચરા, કચરા સ્ટોરેજ ડિપો, સામુદ્રાયિક ક્રડા ધરો યા અચલ યા ચલ અંતરણ સ્થળોં યા કચરે કે દ્વિતીયક સંગ્રહણ કે લિએ નગર પંચાયત દ્વારા નિર્દિષ્ટ સ્થાનોં પર લે જાયા જાએગા

(ii) એસે દ્વિતીયક સંગ્રહણ બિંડુઓ કો કટેનરો (નિર્દિષ્ટ રંગ કે) સે કવર કરિયા જાએગા, જિનસે નિર્માનિત કે લિએ અલગ અલગ સ્ટોરેજ હોયોં:-

(ક) ગૈર-ઝૈવ અપઘટીય અથવા સૂખો કચરા

(ય) ઝૈવ અપઘટીય અથવા ગીલા કચરા

(ગ) ધરેલુ જોખિમપૂર્ણ કચરા

(િલ) પૃથ્યક કિએ ગાએ કચરે કે સંગ્રહણ કે લિએ નગર પંચાયત દ્વારા ચિન્હિત અલગ અલગ કટેનરો કા ઇસ્ટોમાલ નિર્માનિત અનુસાર કરિયા જાયેગા:-

૫. હરાઃ ઝૈવ અપઘટીય કચરે કે લિએ

(३) नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए

(४) काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग सहित और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और हिसी प्रकार का विशेषण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(IV) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस दृश्य से करेगी कि उनको आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वद्य विषयिता न हो।

(V) दृवितीयक संग्रहण डिपुओं भै विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किसी अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में विवित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।

(VI) संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर वी जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र भै कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का धनात्मक कितना है।

(VII) संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका उत्तम इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गए कचरे का खुले वातावरण में कोई दृष्टिभाव न पड़े।

(VIII) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यावरबद्ध समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रूपों के अनुसार अथवा उत्सर्जित कचरा ठोक दृश्य से संगृहीत किया जा सके।

(IX) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे स्पताहिक आधार पर सभी कूडाधरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(X) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढालावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव उपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकिंग केंद्रों को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवर्गों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बैच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकिंग यूनिट पर एक धर्मकाटा और काउटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे

રીસાઇકલ યોગ્ય કચરે કો એસડબ્લ્યૂએમ નિયમો કે પ્રાવધાનો કે અનુસાર દ્વિતીયક બાજાર અથવા રીસાઇકલિંગ યૂનિટો યૂનિટો કો બેચ સકતે હું। અધિકૃત એજેંટ ઔર/યા અધિકૃત દ્વારા બિંકી સે પ્રાપ્ત ધનરાશી રહ્યાને કંઈ હક્કાદાર હોયાં।

#### (x) નિર્દિષ્ટ ઘરેલૂ જોખિમપૂર્ણ કચરે કે લિએ સંગ્રહણ કેદ્દ

(ક) ઘરેલૂ જોખિમપૂર્ણ કચરે કે સંગ્રહણ કેદ્દ ઉપયુક્ત સ્થળ પર સ્થાપિત કિયા જાએગા, જહા નિર્દિષ્ટ ઘરેલૂ જોખિમપૂર્ણ કચરે કો પ્રાપ્ત કિયા જાએગા, ઐસા સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત દિના નિર્દેશો કે અનુસાર યથાસમઝાદ પ્રત્યેક વાર્ડ મેં સ્થાપિત કિયા જાએગા ઔર તસે કચરા પ્રાપ્ત કરને કા સમય અધિસૂચિત કરના હોયા

(ય) નગર પંચાયત અપની એર્લેસી કો યા છૂટગાહી કો યા દાયિત્વ સૌપ સકતી હૈ કિ વહ સમી કચરા ઉત્સર્જકો સે ઘરેલૂ જોખિમપૂર્ણ કચરા પૃથક્કૃત તરીકે સે એકજ કરેં।

(ગ) ઇસ તરહ પ્રાપ્ત કિયા ગયા કચરા સરકાર દ્વારા સ્થાપિત જોખિમપૂર્ણ કચરા નિપટાન કેદો પર અભિગ સે લાયા જાએગા।

#### અધ્યાય-૫

##### ઠોસ કચરે કી દુલાઈ

૭ ઠોસ કચરે કી દુલાઈ નિર્માકિત વાતો કે દ્યાન મે રહે કર કી જાએગી:-

(i) કચરે કી દુલાઈ કે લિએ પ્રયુક્ત વાહન ભલીભાતિ કવર્ડ હોય તાક એકત્ર કચરે કા દુષ્પ્રભાવ સુક્ત વાતાવરણ પર ન પડે। ઇન વાહનો મેં કાર્બનિકટર ઔર સ્પોબાઇલ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન શામિલ હો સકતે હું, જો નગર પંચાયત દ્વારા ધૂની ગઇ પ્રોટોસ્ટેગિકી પર નિર્ભર કરેંગે

(ii) નગર પંચાયત દ્વારા સ્થાપિત સંગ્રહણ કેદ્દ કચરે કે નિપટાન કે લિએ હર રોજ કામ કરેંગે, કૂંડાન યા કંટેનરો કે આસ પાસ કે ક્ષેત્ર કો જાફ રહ્યા જાએગા

(iii) આધાસીય ઔર અન્ય ક્ષેત્રો સે એકત્ર કિયા ગયા પૃથક્કૃત જૈવ અધઘટીય કચરા પ્રોસેસિંગ પ્લાટો જેસે કાસ્પોસ્ટ પ્લાંટ, બાચો-મિનિનેશન પ્લાંટ યા અન્ય કેદ્દ તક કવર્ડ તરીકે સે પહુંચાયા જાએગા।

(iv) જહા કહી પ્રયોજ્ય હો, ડોંડ અધઘટીય કચરે કે લિએ, ઐસે કચરે કી સ્વ-સ્થાને પ્રોસેસિંગ કો વરીયતી દી જાએગી।

(v) એકત્ર કિયા ગયા ગૈર-ડોંડ અધઘટીય કચરા સંબંધદ્વ પ્રોસેસિંગ કેદો અથવા દ્વિતીયક સંગ્રહણ મેં પહુંચાયા જાએગા।

(vi) નિર્માણ ઔર વિદ્વસ જન્ય કચરે કી દુલાઈ નિર્માણ એવ વિદ્વસ કચરા પ્રબધન નિયમ, 2016 કે પ્રાવધાનો કે અનુસૂધ હી જાએગી।

(vii) નગર પંચાયત કચરે કી સમુચીત ઢંગ સે દુલાઈ કે પ્રબધ કરેગા। ભલીયો કો બુહારને સે ઉત્પન્ન કચરા ઔર ભલીયો સે નિકાતી ગઇ ગાદ કામ સમાપ્ત હોને કે તત્કાલ બાદ હટાઈ જાએગી।

(viii) દુલાઈ વાહનો કા ડિજાઇન ઇસ તરહ સે તૈયાર કિયા જાએગા કિ અન્તિમ નિપટારે સે પહુંલે કચરે કે બાર બાર પરિચાલન સે બચા જા સકે।

(ix) કચરા સંગ્રહણ કે લિએ કામ મે લગાએ ગાએ વાહન કચરે કો કેવળ એમ્ટીએસ અથવા એફ્સીટીએસ, જહા કહી પ્રદાન કિએ ગાએ હોં, મે જમા/સ્થાનાંતરિત કરેંગે

- (x) यदि किसी करणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगे, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अंगते निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उत्तरने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएंगे।
- (xi) पिक्सड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा
- (xii) कचरे की ढुलाई के दौरान क्लिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।
- (xiii) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (xiv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रधालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूठादानों से कचरा प्राप्त करेगा।
- (xv) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्षा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट ज्ञान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस लैनात किए जाएंगे।
- (xvi) एमटीएस और एफसीटीएस का उिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उत्तरने में कम से कम समय ले और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।
- (xvii) ठोस कचरे को स्थानान्तरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इट श्रीट रिसे हुए कचरे को खाफ किया जाना चाहिए, तकि कोई रिसाव न बढ़े। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संकरण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
- (xviii) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सौसाटीयों केरे लगाएंगी।

## अध्याय-६

## ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

## ४. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :-

- (i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रधालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा विस्तीर्णी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, तकि ठोस कचरे के क्लिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नान्कित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित भानकों का अनुप्रालन किया जायेगा:-

(क) दुलार्हे की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा औद्योगिक कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लाटों के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयन्त्रों को कचरे के उत्तराधीन अश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईथन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईथन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लाटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्लूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लाट में सीधे इस्तीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्भव अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, पातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अपेक्षित एजेंसियों को देंगा जाए।

#### 9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंकवेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए औद्योगिक कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी औद्योगिक कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मास, पौल्ट्री और मछली व्यापार मैडिया अपले औद्योगिक कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान उत्तराधीन से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

मार्ग्याण्य- 7

#### ठोस कचरे का निपटान

#### 10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ट कचरे और गलियों में झारू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नलियों से निकलने वाली गाढ़ का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत विधिविरुद्ध ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किया

गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा विस्तीर्ण अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैबलिल और सम्बद्ध छाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

#### आध्यार्थ-४

**इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना**

11. ठोस कचरे का संग्रहण, दुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क,-

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, दुलाई और निपटान हेतु सेकाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-१ में विवरित हैं।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा मेयर/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्तिद्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से ३ माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह वसूली के लिए समृद्धि व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वर्षिक और एकमहीने भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अधिक अदा किया जाता है; तो ऐसे में १२ महीने के बाजे १० महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान ५ महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मात्रा की राशि इह महीने के बाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची १ में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः १० प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सकाम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में घूम होने के मामले में सकाम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भौतिक वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के विस्तीर्ण भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची २ में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) ऊपरोक्त छंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशंख निरिक्षक, कर निरिक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष समाज्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नियमित कर सकते हैं। जुर्माना/दड राशि अनुसूची २ में दी गई है।

(घ) अनुसूची २ में वर्णित जुर्माना अथवा दड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः ५ प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना भौंके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान भौंके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की आति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

#### अध्याय-७

##### प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(i) कूड़ा फेकने पर पाबंदी

(ए) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़दानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फेलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक कैदों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की गतिशीलता, बत्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संश्लेषण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फेलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़दानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सुवित्त या विकल्प संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या चाली के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेलेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी द्रुक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं डालाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो तकि सड़क फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी कुता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं भी शीर्षक प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नलियों आदि में कचरे का निपटान कोई व्यक्ति किसी भाली/नदी/खुले तालाब/जल निकार्यों में गंदगी नहीं डालेगा।

- (I) कचरे को जलाना . सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।
- (II) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वाभित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नलिया/गटर सड़क बिजारा समिल हैं, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।
- (IV) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदृशनियां, सर्कस, भेले, राजनीतिक भेलिया, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सारकृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदृशनों और प्रदृशनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्थ्यता सुनिश्चित करे।
- (V) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जोध की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हजारा नहीं होगा यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पंचायत के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सकम्भ प्राधिकारी द्वारा तय विभा गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- (VI) छाली प्लॉट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विघ्नास कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नलिखित ढंग से निपटेगा -
- (क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक/अधिकारी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिकारी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।
- (ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।
- (ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है -
- (प) ऐसे परिसर में प्रदेश कर कचरे की साफ करना, और (पप) अधिकारी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नैपकिन तथा छायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व -

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन काच, प्लास्टिक बैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले बैड मालिकों को कचरा प्रबंधन

प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी, नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(४) ऐसे सभी ब्रैड मालिकों को, जो गैर-जैव औपचारीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(५) सेनिटरी नेप्किन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किया हुद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पात्र या ऐपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेप्किन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(६) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैमिंग और उत्पोजात के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

#### 14. नगर पंचायत के दायित्व :

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूगत्त में सभी साझा भलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उदयनों, बांगों, भलियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। वह इसके लिए जूनूद संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा धोखित संचाहन कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद बाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और बाहनों के अल वा, अनुबंध के आधार पर ग्राहवेट पर्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी शाखादार व्यवस्था का सहारा ले सकता है, इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी धार्णिज्यक क्षेत्रों ऐसे धार्णिज्यक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ लगाने की आवश्यता है।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एवं सभी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों बस अड्डों, धार्णिक स्थलों और वणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदाढ़ों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत विकैदीकृत और नियमित ठंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वाड़ में एक वाड़ अधिकारी नियूक्त करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पेशावर्धरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए द्वासफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, सगड़, दुलाई, प्रस्तकरण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष ईक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वाड़ निर्धारित मानवड के आधार पर स्वीपिंग बैटस में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुनितसगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग करने

में असमंज्स होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बैट का निरीक्षण दिला निर्देशों के अनुसार नियोजित दैनिक आधार पर भुपरवाइलिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गाँवी क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झांझ लगाने और नलियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अधिकार के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जनों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएस नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष चल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कधरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्वाक्षर पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेन्ट्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-प्रियोनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध देवसाङ्कटों में प्रकाशित करना अथवा संपति कर आदि में छोट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही समझ हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा अनौपचारिक कधरा रीसाइकिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(x) नगर पंचायत ठोस कधरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचाल और औपचारिक झनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कधरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कधरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यवित्रित सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट और कैट दस्तावेज, रेमोट, समुचित फुटवेशर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कधरा परिधान कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यवित्रित सरका के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कधरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैनफिल साइट पर कोई दृथिटा होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच - अध्यक्ष, उपअध्यक्ष द्वारा प्रधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों में और और ठोस कचरे के संग्रहण, दुलार्ड, प्रोसेसिंग और निपटान से सबैधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह

યह સુનિશ્ચિત કિયા જા સકે કી એસડબ્લ્યૂએમ નિયમો ઔર ઇન ઉપ-નિયમો કે વિભિન્ન પ્રાવધાનોં કા પાલન હો રહા હૈની।

(xv) નગર પંચાયત અપને મુખ્યાલય મેં કોલ સેંટર કી સ્થાપના કે જરિએ સાર્વજનિક શિકાયત નિવારણ પ્રણાલી (પીજીઆરએસ) વિકસિત કરેગા ઇસ પીજીઆરએસ મેં એસએમએસ આધારિત સેવા, મોબાઇલ અપલેકેશન અથવા વૈબ આધારિત સેવાએ શામિલ હો સકતી હૈની।

(xvi) નગર પંચાયત એસડબ્લ્યૂએમ નિયમો ઔર ઉપ-નિયમો કે કાર્યાન્વયન સે સમ્બંધ્ય કર્મચારીઓ કી ઉપસ્થિકત દર્જ કરને કે લિએ કાર્ડ પ્રોદ્યોગિકિયા/આઇસીટી પ્રણાલી કાયમ કરેગા તથા એસી પ્રણાલી કો વૈતન/દિહાડા/પરિશ્રમિક કે સાથ એકીકૃત કરને કે પ્રયાસ કરેગા।

(xvii) નગર પંચાયત એસડબ્લ્યૂએમ નિયમો ઔર ઉપ-નિયમો કે કાર્યાન્વયન પહુંચ અધિક પારદર્શિતા ઔર સાર્વજનિક પહુંચ સુનિશ્ચિત કરને કે લિએ નગર પંચાયત અપની વૈબસાઇટ સે સારી આવશ્યક સૂચનાએ પ્રદાન કરેગા।

(xviii) નગર પંચાયત એસડબ્લ્યૂએમ નિયમો મેં વર્ણિત સભી અન્ય દાયિત્વ પૂરે કરેગા, જો ઇન ઉપનિયમો મેં વિશેષ રૂપ સે ઉલ્લિખિત નહીં કિએ શકે હૈની।

#### અધ્યાય-10

##### વિવિધ

15. ઇને ઉપનિયમો કી વ્યાખ્યા યા કાર્યાન્વયન મેં કોઈ સંદેહ યા કઠિનાઈ આને કી સ્થિતિ મેં ઉસે આધ્યાત્મ, નગર પંચાયત કે સમજી રેખા જાએગા, જિસકા નિર્ણય એસે મામલે મેં અંતિમ હોયા।

16. સરકારી નિકાયોં કે સાથ સમન્વય : નગર પંચાયત અન્ય સરકારી એંડસિયો ઔર પ્રાધિકરણો કે સાથ સમન્વય કરેગા, તાકિ ઇન ઉપનિયમો કા અનુપાતન એસે નિકાયોં કે અધિકાર હેતુ યા નિયંત્રણ મેં આને વાલે ઇલાકોં સુનિશ્ચિત કિયા જા સકે। કોઈ કઠિનાઈ હોને કી સ્થિતિ મેં ઉત્તરાખણ્ડ સરકાર કે મુખ્ય સંદેશ કે સમજી વિચારાધી રેખા જાએગા।

17. સલામ પ્રાધિકારી ઠોસ કચરા પ્રબંધન નિયમ 2016 ઔર ઇન ઉપ-નિયમો કે સમુચ્છિત કાર્યાન્વયન કે લિએ સમય સમય પર સામાન્ય યા વિશેષ આદેશ જારી કર સકતે હૈની।

#### ઠોસ કચરા પ્રબંધન કે લિએ ઇસ્તોમાલકર્તા શુલ્ક

૧	૨	૩
ક્રમાંક	અપશિષ્ટ ઉત્પાદક કી શૈળી/અપશિષ્ટ કા પ્રકાર	પ્રતિમાહ સેવા શુલ્ક(ચૂજર ચાર્જ રૂપયે મેં)
1.	ગરીબી રેખા સે નીચે કે ઘર(બી પી એલ કાર્ડ ધારકે)	કચ્ચી ઝોપડી રૂ 10.00, પક્કા માકાન રૂ 20.00
2.	ઉપરોક્ત કે અંતિરિક્ત ઘર	રૂ 30.00
3.	સંભિ એવું ફલ વિક્રેતા	ઠેલી પર ફેરી મેં રૂ 10.00 પ્રતિદિન, દુકાન એવું ફડ પર રૂ 20.00 પ્રતિદિન
4.	રેસ્ટોરેન્ટ	છોટે રૂ 300.00, મધ્યમ રૂ 800.00 તથા બઢે રૂ 2000.00

5.	होटल/लॉगिंग/गेस्ट हाउस	₹ 1000.00
6.	ब्रातघर(चेरिटेबिल) ब्रातघर(नॉन-चेरिटेबिल)	₹ 1000.00 प्रति उत्सव
7.	बेरी	₹ 100.00
8.	ग्रॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	₹ 1000.00
9.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक ₹100.00, पैथोलॉजी ₹ 500.00
10.	दुकान/व्याच की दुकान	₹ 50.00,
11.	वर्कशॉप	₹ 300.00
12.	कबाढ़ी	₹ 200.00
13.	जूस/गन्ज का रस विक्रेता	₹ 10.00 प्रतिदिन
14.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 1000.00 होटलों में, विवाह ₹ 5000.00 प्रति उत्साह
15.	द्वान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50धन मी० तक ₹ 200.00, 1.0धन मी० तक ₹ 400.00, 3.0धन मी० तक ₹ 1000.00, 6.0धन मी० तक ₹ 2000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी० ₹ 200.00 अधिक
16.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्थान की स्थिति के अनुसार)	₹ 10.00 से ₹ 100.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की  
स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10% प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार  
(एलपीएससी) लगाया जाएगा।

### अनुसूची-2

#### जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों	आवासीय 6000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल फैस्टिवल हाल पार्टी लान प्रदर्शनी और सेल स्थल	200 10,000

		के अनुसार सौपने में विफल रहना	5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों सिनेमाघरों पर्स सामुदायिक हॉल भल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	5000 500
			फिसमीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथ्यकरण तरीके से न रखना।	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1. सड़क/गली में कूड़ा फेकना थूकना  2. अहाना पैशाब करनाएँ जानवरों को धारा खिलाना कपड़े थोना बाहन थोना गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता  उल्घनकर्ता एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।	200 से 600 500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ए) और (घ)	नियमनुसार सेमिटरी कथरे का निपटान करने में विफल रहना।	आवासीय गैर-आवासीय/बल्क ज़िक्रेर	200 500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कथरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय गैर-आवासीय/बल्क ज़िक्रेर	1000 5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में छताना	उल्घनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन निए बिना किसी गैर लाहसौसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों अधिक की आगीदारी	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा	10,000

		के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	आयोजित की हो	
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कधरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भ्रष्टारन डिपो या फाब्र या वाहन में डालने से विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कधरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कधरे का निपटान में विफलता	निवासी काल्याण	10,000
			एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	
			बजार एसोसिएशन, संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कधरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कधरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित ऐकेजिंग कधरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की विक्री	विनिर्माता और/या ब्रॉड ॲनरस्वामी	1,00,000

		अथवा विपणन		
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और बोर्ड स्वामी और विपणन कपनियाँ	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियाँ, पहाड़ियाँ, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कालाज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, फैन, टैट्रा ऐक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फेंकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/अतिथियाह में बोर्ड संग्रह अवश्यक स्थापना करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/ अतिथियाह स्वामी	1000
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रदर्शनियाँ, सर्कस, मेले, राजनीतिक ऐलिया, वाणिजिक, पार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

ठ० (अल्पष्ट)  
अधिशासी अधिकारी,  
बंगर पंचायत पुरोला।

ठ० (अल्पष्ट)  
अध्यक्ष,  
बंगर पंचायत पुरोला।